नई दिल्ली ■ शुक्रवार 30 जनवरी 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 303 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 विमान हादसों में नेताओं की असमय... | 07 ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना ही इतिहास रचना चाहते हैं जोकोविच | मोना सिंह और बरुण सोबती की सीरीज 'कोहरा 2' ... 08

सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव की परिभाषा से संबंधित यूजीसी के नियम पर रोक लगाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हालिया नियम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी।

इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए। उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को

बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थानों द्वारा 'समानता समितियां' गठित करने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 में यह अनिवार्य किया गया है कि इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से तथा दिव्यांग एवं महिला सदस्य शामिल होने चाहिए।

नया विनियम यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 का स्थान लेने के लिए अधिसूचित किया गया था। 2012 के नियम मुख्य रूप से परामर्श वाली प्रकृति के थे। इन याचिकाओं में इस विनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई कि जाति-आधारित भेदभाव को सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव के रूप में ही परिभाषित किया गया है।

याचिकाओं में कहा गया है कि 'जाति-आधारित भेदभाव' के दायरे को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित करके यूजीसी ने प्रभावी रूप से 'सामान्य' या गैर-आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को संस्थागत संरक्षण और शिकायत निवारण से वंचित कर दिया है जिन्हें उनकी जातिगत पहचान के आधार पर उत्पीड़न या पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है। इन नियमों के खिलाफ देश में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें छात्र समूहों और संगठनों ने इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग से कोई समझौता नहीं होना चाहिए : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के नैतिक उपयोग से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े कौशल विकास, प्रतिभा निर्माण और डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने गुरुवार को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कार्यरत उद्योग प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ संवाद किया। यह संवाद आगामी भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन के अनुरूप आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े नवाचारों को प्रस्तुत करना और भारत के इस मिशन के लक्ष्यों को गति देना है। इस अवसर पर उद्योग प्रमुखों और विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक में आत्मनिर्भर बनने के भारत के लक्ष्य का समर्थन किया और वैश्विक स्तर पर भारत को अग्रणी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने डेटा सुरक्षा और तकनीक के लोकतंत्रीकरण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत को एक ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना चाहिए, जो पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित हो।

उन्होंने कहा कि भारत का यह तंत्र देश के चरित्र और मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को अपनाने और उसे राष्ट्रीय विकास में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया।

एक हजार करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की छापेमारी

कोलकाता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हजार करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की। अलीपुर समेत कोलकाता के कई इलाकों में एक साथ सीबीआई की छापेमारी चल रही है। यह कार्रवाई एक फाइनेंस कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई के प्रमोटरों के खिलाफ की जा रही है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सीबीआई की टीमें संबंधित फाइनेंस कंपनी के प्रमोटरों के आवास और कार्यालयों में तलाशी ले रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। सीबीआई सूत्रों ने

बताया कि वर्ष 2014 से 2020 के बीच एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से ऋण लेने के नाम पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की गई। पूर्व कोलकाता स्थित इस फाइनेंस कंपनी के खिलाफ बैंक प्रबंधन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने जांच शुरू की।

बीजापुर में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से एके-47 राइफल, 9 एमएम पिस्टल और गोला-बारूद बरामद किया गया है। बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना राज्य के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों की बटालियन सक्रिय है। विशेष रूप से पामेड़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता ज्यादा देखी जा रही है। इसी पामेड़ इलाके में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि बीजापुर जिले के दक्षिणी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के बाद डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड) जवानों को सर्चिंग अभियान पर रवाना किया गया। इसी दौरान जंगल में नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी।

उप्र कैबिनेट : पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों का होगा स्थायी पुनर्वासन

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में रह रहे हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनपद मेरठ से जुड़े इस प्रकरण को मंजूरी दी गई।

यह मामला जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गोसाई का है, जहां पूर्वी पाकिस्तान से

विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवार झील की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार इन सभी 99 परिवारों का पुनर्वासन जनपद कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में किया जाएगा।

ग्राम भैंसाया में पुनर्वास विभाग के नाम दर्ज 11.1375 हेक्टेयर (27.5097 एकड़) भूमि पर 50 परिवारों को तथा ग्राम ताजपुर तरसौली में पुनर्वास विभाग के नाम अंकित 10.530 हेक्टेयर (26.009 एकड़) भूमि पर शेष 49 परिवारों को बसाया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 0.50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। यह भूमि प्रीमियम अथवा लीज रेंट पर 30 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी, जिसे आगे 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार पट्टे की अधिकतम अवधि 90 वर्ष होगी।

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार
अतुल्य!भारत

भारत पर्व 'वोकल फॉर लोकल' को अपनाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, विविधता का सम्मान करने और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का एक पर्व है।
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

परंपरा की हर तान
हर उत्सव की जान

यहां आप देख पाएंगे एक ही छत के नीचे भारत देश की सभी पुरानी प्रदर्शन कलाएँ। यहां आप शास्त्रीय रागों से लेकर जीवंत लोक नृत्यों, मधुर संगीत से लेकर दमदार नाटकों का आनंद लेकर संगीत और अभिनय कला की अद्भुत जुगलबंदी का अनुभव कर पाएंगे। आइए, फिर से उन परंपराओं को जियें जो हमें एक सूत्र में बांधती हैं।

भारत पर्व 2026
26 – 31 जनवरी

लाल किला, दिल्ली
30 – 31 जनवरी
दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक

प्रवेश निशुल्क। कृपया अपना पहचान पत्र साथ लाएं।

गणतंत्र दिवस परेड की झांकियाँ। | सशस्त्र बलों के बैंड की प्रस्तुतियाँ | सांस्कृतिक प्रदर्शन | शिल्प बाजार | स्टूडियो किचन | बहु-व्यंजन फूड कोर्ट

CBC 42101/13/0010/2526

दंपति की जहरीला पदार्थ खाने से मौत, तीन बच्चे अस्पताल में भर्ती

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक तृतीय क्षेत्र से एक अत्यंत दुखद और संवेदनशील मामला सामने आया है। 28-29 जनवरी की मध्य रात्रि में पारिवारिक कारणों के चलते एक दंपति द्वारा कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लेने की घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। इस दर्दनाक घटना में पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनके तीन मासूम बच्चे उपचार के बाद खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान श्रवण पुत्र अमरनाथ पाल एवं उनकी पत्नी नीलम के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से ग्राम असरवाल कला, थाना एयरपोर्ट, जनपद प्रयागराज के निवासी थे और वर्तमान में ग्राम सादुल्लापुर, थाना ईकोटेक तृतीय क्षेत्र में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि किसी पारिवारिक विवाद अथवा तनाव के चलते दोनों ने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा सभी को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने पति-पत्नी को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में दंपति के तीन बच्चे- वैष्णवी (उम्र लगभग 10 वर्ष), वैभव (उम्र लगभग 8 वर्ष) और लाडो (उम्र लगभग 4 वर्ष) भी प्रभावित हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार, तीनों बच्चों की हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। सूचना मिलने पर थाना ईकोटेक तृतीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ की। पुलिस द्वारा मृतक दंपति के शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सके।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल, पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि दंपति ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया।

प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, अवैध रूप से बने आठ रिहायसी टावर किये सील

ग्रेटर नोएडा। अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को सुबह बड़ी कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने खेड़ा चौगानपुर गांव में खसरा संख्या 109 पर बने 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया। इन टावरों में 100 से अधिक फ्लैट बने हुए थे, जो बिना किसी अनुमति और नक्शा पास कराए अनधिकृत रूप से तैयार किए गए थे। कार्रवाई के समय सभी फ्लैट खाली पाए गए।

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार यह भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आती है। यहां बिल्डरों द्वारा बिना किसी स्वीकृति के बहुमंजिला रिहायशी टावर खड़े कर दिए गए थे। न तो निर्माण की अनुमति ली गई थी और न ही किसी प्रकार का लेआउट या भवन मानचित्र पास कराया गया था। पहले भी प्राधिकरण की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। इसके बावजूद अवैध निर्माण कार्य जारी रहा, जिसके बाद अब सीलिंग की कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्हीं निर्देशों के तहत भूलेख विभाग और परियोजना विभाग की संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव की निगरानी में की गई।

मौके पर ओएसडी अभिषेक पाठक, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम, प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला, स्थानीय पुलिस और प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई। प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सीलिंग, ध्वस्तीकरण और कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि ग्रेटर नोएडा में जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें। अवैध कॉलोनियों या गैरकानूनी निर्माण में निवेश कर लोग अपनी गाढ़ी कमाई जोखिम में न डालें। प्राधिकरण ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे और मामलों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

संगठन, संघर्ष और नेतृत्व का संगम बनेगा आरएलडी महिला अधिवेशन

नोएडा। राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ द्वारा आगामी 1 फरवरी को आयोजित होने वाले महिला अधिवेशन को सफल बनाने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को नोएडा मीडिया क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में ग्रेटर नोएडा स्थित अवध ग्रीन्स में होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों, उद्देश्य और कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा साझा की गई। अधिवेशन की संयोजिका सोनिका आनंद ने बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को सशक्त बनाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि महिला अधिवेशन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी चारू चौधरी तथा राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष इंदिरा कपिलावे भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। इसके अतिरिक्त कई राज्यों से महिला प्रकोष्ठ की वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता अधिवेशन में भाग लेंगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी ऋचा सिंह ने कहा कि महिला अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संगठनात्मक नेतृत्व के लिए प्रेरित करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें निर्णायक भूमिका में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि महिला प्रकोष्ठ लगातार समाज में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है और यह अधिवेशन उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

फर्जी लैप्स बीमा कॉल सेंटर का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

नोएडा। भारत देश में रहने वाले लोगों की लैप्स बीमा पॉलिसी के रुपये ब्याज सहित वापिस दिलाने के नाम पर जनता से पैसों की ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेन्टर का पर्दाफाश करते हुए थाना फेस-वन पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगों के कब्जे से 1 लैपटॉप, 8 स्मार्ट मोबाइल फोन, 8 कीपैड मोबाइल, 3 पीएनटी फोन व 15 कालिंग डाटा शीट बरामद की है। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने अब तक लोगों से लैप्स बीमा पॉलिसी की रकम दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है।

एडीसीपी नोएडा शैव्या गोयल ने बताया गुरुवार को थाना फेस-1 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेन्स व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से लैप्स बीमा पॉलिसी के रुपये वापस दिलाने के नाम पर पैसे ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेन्टर का पर्दाफाश करते हुए 3 साइबर अपराधी वरुण शर्मा पुत्र वीरेश चन्द्र शर्मा, मदन गुप्ता पुत्र स्व. रामसनेही लाला गुप्ता तथा प्रदीप वर्मा पुत्र सुरेन्द्र शाह को नोएडा सेक्टर-10 से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों द्वारा अब तक कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गयी है, जिसमें करीब 20 बैंक खातो में ठगी के करीब 1 करोड़ 20 लाख रूपये फ्रीज कराये गये हैं।

एडीसीपी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह भारत देश में रहने वाले लोगों को लैप्स बीमा पॉलिसी के रुपये वापस दिलाने के नाम पर पैसे ठगकर फर्जी बैंक खातों में धनराशि ट्रान्सफर कराते थे। अभियुक्त फर्जी बैंक खातों में लेनदेन करते थे। उन बैंक खातों में जमा लाखों रूपये फ्रीज कराये गये है। अभियुक्तों से बरामद लैपटॉप में ठगी से सम्बन्धित डाटा शीट्स पाए गये है। जो अभियुक्त वरुण द्वारा 10,000/- रूपये में 5,000 व्यक्तियों का डाटा प्राप्त किया गया और कम्पनी के कर्मचारियों में बांट दिया। उन्होंने बताया कि अभियुक्तगण झांसा देकर 10,500/- रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक का इन्वेस्ट करा लेते थे तथा ठगी की रकम आपस में बांट लेते थे। अभियुक्तगण रियल स्टेट में इन्वेस्टमेन्ट व LIC की पॉलिसी को कम समय में मैच्योर कराके पूरी रकम वापस कराने के नाम पर भी ठगी करते थे। इस प्रकार की ठगी से सम्बन्धित 20 से अधिक शिकायते NCRP पोर्टल पर विभिन्न राज्यों मे दर्ज है। अभियुक्त ठगी के रूपयों से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा(बैटिंग) खेलते थे जिसमे 20 प्रतिशत पर खाता खरीदकर 80 प्रतिशत रूपये अपने बैंक खातो में जमा करा लेते थे।

यूजीसी को लेकर बोले अखिलेश: दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ ना हो अन्याय

नोएडा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को नोएडा दौरे के दौरान एक बातचीत में यूजीसी को लेकर कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि ₹दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो₹ उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहां पर हर पहलू पर बहस होगी।

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वर्ष 2012 में रेगुलेशन आया था। उसमें कमी क्या रही और उसमें क्या-क्या फैसले हुए, या किस तरह के

यूनिवर्सिटी और वहां के लोगों ने उसे स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि 2012 के रेगुलेशन से हमने क्या सीखा और 2026 के रेगुलेशन में क्या होगा। उन्होंने कहा कि जब हमारा संविधान कहता है कि कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर भी भेदभाव होता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने देश में सबसे ज्यादा मेट्रो रेल बनाई है। उन्होंने दावा किया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से नोएडा के जोड़ने वाली मेट्रो रेल सपा सरकार में बनी। उन्होंने कहा कि लखनऊ में सपा सरकार ने मेट्रो रेल बनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में मेट्रो रेल नहीं बनवा रहे हैं।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री पानी में मेट्रो चलवाने की बात कर रहे हैं। वह सड़क पर मेट्रो चला नहीं पा रहे हैं, पानी में मेट्रो चलाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में मेट्रो बनाने के लिए डीपीआर और बजट दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारस में मेट्रो नहीं बना रहे हैं।

नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गहरे गढ़े के पानी मे डूबकर हुई मौत के मामले में उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग काफी होशियार हैं। वे लोग देश चला रहे हैं। घटना किसकी वजह से हुई, सवाल घटना का नहीं है। सवाल यह है कि वह बच्चा कार के ऊपर खड़ा होकर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मदद नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे वे लोग ठंडे पानी की वजह से बचाने नहीं गए।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी मामले को मैनेज कर लिया है। इस पर चर्चा भी नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दोपहर बाद गौतमबुद्ध नगर के दौरे पर आए थे। उन्होंने सपा नेता मोहित नागर के घर पर पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनाव, किसानों की समस्या और छात्रों की समस्याओं पर चर्चा की।

यूजीसी के नए नियमों का विरोध में इस्तीफा दिया

ग्रेटर नोएडा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नए नियमों का विरोध जारी है। धरना प्रदर्शन के साथ भाजपा के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। जेवर क्षेत्र के पांच बूथ अध्यक्ष और एक शक्ति केंद्र प्रभारी ने सामूहिक रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष के अपना इस्तीफा भेजा। अन्य पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा देने की चेतावनी दी। बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी ने जिलाध्यक्ष को भेजे सामूहिक इस्तीफा पत्र में लिखा कि यूजीसी अधिनियम में सवर्ण समाज का शोषण करने वाला और अत्याचार करने वाला दर्शाया गया है। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं, सवर्ण समाज के अन्य लोगों का कहना है कि जब तक नए अधिनियम को वापस नहीं लिया जाएगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

सवर्ण समाज ने निकाली यूजीसी विरोध यात्रा, सौंपा ज्ञापन

नोएडा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों एवं प्रावधानों के विरोध में आज सवर्ण समाज गौतमबुद्धनगर द्वारा जीवन अर्पण सामाजिक सेवा संस्था के बैनर तले यूजीसी विरोध यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी संख्या में छात्र शामिल रहें। यूजीसी विरोध यात्रा नोएडा स्टेडियम गेट नंबर-4 से शुरू होकर सेक्टर-19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर समाप्त हुई। जहां सिटी मजिस्ट्रेट को नये यूजीसी कानून को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया।

इस दौरान कार्यक्रम संयोजक पुष्कर शर्मा ने बताया कि यूजीसी द्वारा लाया गया यह कानून छात्र विरोधी है। जहां शिक्षण संस्थानों में बच्चे जाति

विरोधी भावनाओं को भूलकर पढ़ते हैं। अब इस काले कानून की वजह से आपसी भेदभाव के मार्ग पर अब वह भटक कर अपना भविष्य खराब कर सकते हैं । वहीं दीपांशु शर्मा ने कहा कि यूजीसी का नया कानून छात्र विरोधी कानून है। जहां शिक्षा संस्थानों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते है वहां सरकार द्वारा कुछ चंद जातियों के हित के लिए लाया गया कानून छात्रों का भविष्य खराब करने का कार्य करेगा।

उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं को देखते हुए इस कानून में आवश्यक सुधार जरूरी है। इस दौरान साधना शर्मा, अनमोल सहगल, एडवोकेट अंकुश शर्मा, संदीप पाठक, राहुल शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, हैप्पी पंडित, हर्ष नंबरदार, गुन्नी पंडित, आकाश चौहान, सतेंद्र मिश्रा, विपिन चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

नोएडा प्राधिकरण ने स्वच्छता कार्यों में लापरवाही पर चेताया, अधिकारी और एजेंसियों को सख्त निर्देश

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रतिभाग किया जाता है। शहर को और भी अधिक स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने एवं स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ।

इस संबंध में सीईओ कृष्ण करुणेश ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। यदि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में आज सेक्टर-91 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में जन स्वास्थ्य एवं सिविल विभाग के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ओएसडी

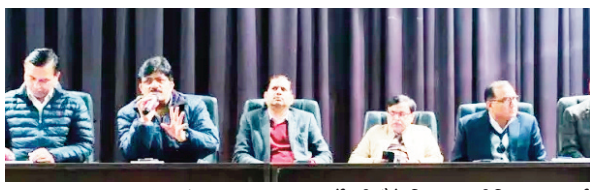

जन स्वास्थ्य क्रांति शेखर सिंह, महाप्रबन्धक एसपी सिंह, महाप्रबन्धक एके अरोड़ा, उप महाप्रबन्धक विजय रावल, इन्दु प्रकाश सिंह, गौरव बंसल, आरके शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

बैठक में मैसर्स एजी एनवायरो को निर्देशित गया कि कूड़ा संग्रहण वाहन नोएडा क्षेत्र में सभी घरों से 100% वेस्ट कलेक्शन करेंगे। यदि वेस्ट कलेक्शन कार्य में लापरवाही की जाती है तो एजेंसी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।मैकेनिकल स्वीपिंग एजेंसीज को निर्देशित किया गया कि सभी मुख्य मार्गों की मैकेनिकल स्वीपिंग का कार्य नियमित रुप से कराया जाए। यदि सफाई कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं किया जात है और कार्य में लापरवाही की जाती है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। वहीं सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि सफाई कार्य करते समय आवश्यक सावधानी बरतें एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। साथ ही सुपरवाईजरों को निर्देशित किया गया कि समस्त सुपरवाईजरों के पास एवं कार्यरत कर्मचारियों के पास उनका पहचान पत्र और ड्रेस पहनकर कार्य करें। साथ ही सुपरवाईजर अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन सुनिश्चित करें कि रोड/केसी ड्रेन/फुटपाथ / सर्विस रोड की नियमित सफाई की जा रही है या नहीं। इसके अलावा सेक्टरों व ग्रामों में लगने वाले साप्ताहिक मार्केटों की सफाई उसी दिन रात्रि के समय कराई जाए। मार्केट एवं Vendor Zone में सभी दुकानदारों व ठेले वालों को दो डस्टबिन रखने के लिए जागरूक करे। जो Vendor हरा/नीला डस्टबिन का प्रयोग नहीं करेंगे उनका सर्वे कराकर उनके विरूद्ध पेनल्टी लगाने की कार्यवाही की जाए ।

इसके साथ ही सिविल विभाग को सफाई कार्य में जन स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया। जिन सुपरवाईजरों के कार्यक्षेत्र में गंदगी पाई जायेगी, ऐसे सुपरवाईजर के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

विकास की नेतृत्वकर्ता हैं महिलाएं: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 'शक्ति संवाद' कार्यक्रम में हुईं शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि आज महिलाएं केवल सुझाव देने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। यही सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां भारत मंडपम में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा आयोजित 'शक्ति संवादः दो दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण' कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से आई महिला आयोग की अध्यक्षों, सदस्यों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका पर विस्तार से अपने विचार रखे। इस अवसर पर एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया रहाटकर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव बी. राधिका चक्रवर्ती समेत आयोग की अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के उद्देश्य लीगल अवेयरनेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल, पॉलिसी कंसल्टेशन और क्षमता निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास देश की करोड़ों बेटियों में साहस और आत्मविश्वास जगाने का माध्यम बनेंगे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, उनका आर्थिक सशक्तीकरण और निर्णय व नेतृत्व में उनकी सहभागिता जैसी तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उठाए गए ठोस कदमों का उल्लेख करते हुए बताया कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते सुरक्षा मानकों का पालन हो। कामकाजी महिलाओं, विशेषकर श्रमिक बहनों के बच्चों के लिए 500 'पालना केंद्र' स्थापित किए गए हैं, ताकि वे निश्चिंत होकर काम कर सकें। आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महिलाओं को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे वे अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। सुरक्षा के क्षेत्र में 10,000 अत्याधुनिक कैमरे और एक लाख स्मार्ट सेंसर्ड एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 53 नए न्यायिक पदों को स्वीकृति देकर फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'शक्ति संवाद' केवल थीम नहीं, बल्कि महिलाओं की सामूहिक शक्ति और आपसी संवाद से भविष्य का मार्ग तय करने का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत आज महिला सशक्तीकरण से आगे बढ़कर वुमन-लेड गवर्नेंस और वुमन-लेड डिसीजन मेकिंग के दौर में प्रवेश कर चुका है। गणतंत्र दिवस परेड में, सशस्त्रबलों में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका, साहसिक प्रदर्शनों, राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी परिवार से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची महिला की यात्रा और संसद में महिला नेतृत्व, ये सभी उदाहरण भारत में महिलाओं की बढ़ती निर्णायक भूमिका को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने 'बेटी बचाओ' से 'बेटी पढ़ाओ' और अब 'बेटी बढ़ाओ' तक के सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश उस चरण में है जहां बेटियों के सपनों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसरों का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग वह शक्ति और भरोसे का केंद्र है, जहां पीड़ित महिला सबसे पहले सहायता की उम्मीद करती है और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस तक समय पर पहुंचकर न्याय, संबल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने देश के दूरदराज क्षेत्रों खासकर उत्तर-पूर्वी राज्यों से आई महिला आयोग अध्यक्षों के समर्पण और जज्बे की सराहना की और महिला आयोग के 34 वर्षों के संघर्षपूर्ण और प्रेरक सफर को नमन किया।

पंजाब के डीजीपी ने आतिशी मामले पर रिपोर्ट राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंपी

नई दिल्ली। पंजाब के डीजीपी ने आतिशी मामले पर रिपोर्ट को आवश्यक स्वीकृति के लिए राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दिया है और दिल्ली विधानसभा को इससे अवगत कराया है। विधानसभा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली विधान सभा सचिवालय को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से लिखित उत्तर प्राप्त हुआ है। यह उत्तर दिल्ली विधानसभा सचिवालय के 23 जनवरी को भेजे गए पत्र के संदर्भ में है। पत्र में जालंधर पुलिस की प्राथमिकी (एफआईआर) के संबंध में कल तक लिखित जवाब मांगा गया था। अपने उत्तर में पंजाब के डीजीपी ने सूचित किया है कि इस मामले पर उनका जवाब आवश्यक स्वीकृति हेतु पंजाब सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अग्रेषित कर दिया गया है। डीजीपी ने यह भी बताया है कि जालंधर के पुलिस कमिश्नर से प्राप्त लिखित जवाब भी अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। डीजीपी पंजाब के माध्यम से भेजे गए उत्तर में जालंधर के पुलिस आयुक्त ने उल्लेखित किया है कि प्राथमिकी से संबंधित लिखित जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है तथा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उसे दिल्ली विधान सभा सचिवालय को भेज दिया जाए।

दिल्ली की सीएम ने ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्ड कप की विश्वविजेता टीम को किया सम्मानित

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्ड कप की विश्वविजेता टीम का मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये बेटियां संकल्प, साहस और आत्मविश्वास की प्रेरक मिसाल हैं। इनकी उपलब्धियों पर देश को गर्व है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्ड कप की विश्वविजेता टीम का हौसला बताता है कि मजबूत इरादों के सामने कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। इन्होंने अपने खेल से यह सिद्ध किया है कि प्रतिभा और परिश्रम ही असली पहचान बनाते हैं। उन्होंने इन सभी बेटियों को भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये आगे बढ़ती रहें, नए कीर्तिमान स्थापित करती रहें और भारत का गौरव ऊंचा करती रहें। इस अवसर पर टीम के कोच और ब्लाइंड एसोसिएशन के सदस्यों से भी मौजूद रहे।

पायलट सुमित कपूर का अंतिम संस्कार, स्थानीय लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। दिल्ली के राजौरी गार्डन की इस अनजान सी गली में बृहस्पतिवार को गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कैप्टन सुमित कपूर इसी इलाके में रहते थे जो एक दिन पहले बारामती विमान दुर्घटना में मारे गए। इसी हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की भी जान चली गई थी।

शोकाकुल परिजनों की नम आंखों और गमगीन माहौल के बीच बृहस्पतिवार को पायलट सुमित कपूर का अंतिम संस्कार किया गया। सुमित कपूर के पार्थिव शरीर को उनके घर के बजाय सीधे पंजाबी बाग श्मशान घाट ले जाया गया। इसलिए उनके परिवार के लोग और मित्र अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पर एकत्रित हुए। कई शोक संतप्त लोगों ने करीब 50 साल के कपूर को एक मिलनसार पड़ोसी और एक समर्पित पेशेवर के रूप में याद किया जिनकी अचानक मृत्यु से पूरा इलाका सदमे में है। उनके करीबी दोस्त अरविंद कुमार ने बताया कि कपूर समुदाय के कामों में पूरी तरह से शामिल रहते थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे।

कुमार ने कहा, सुमित बहुत अच्छे इंसान और मिलनसार पड़ोसी थे। उन्होंने कहा, उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा जो खुद भी पायलट है, एक बहू और एक पोता है। वे इसी इलाके में एक घर बनवा रहे थे और फिलहाल पास में ही किराए पर रह रहे थे।ः कुमार ने कहा कि दुर्घटना की खबर से निवासियों को गहरा सदमा लगा है।

कैप्टन सुमित कपूर के पास 15,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। कपूर बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के पायलट-इन-कमांड थे। पवार और कपूर के अलावा, सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विदिप जाधव और विमान परिचारिका पिंकी माली की भी इस हादसे में मौत हो गई।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने की 'यूथ फॉर गवर्नेंस' की शुरुआत

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री एवं जनकपुरी विधायक आशीष सूद ने गुरुवार को 'यूथ फॉर गवर्नेंस (वाईएफजी)' पहल का औपचारिक शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण से प्रेरित है जिसमें उन्होंने गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से एक लाख युवाओं को सरकार से जोड़ने का आह्वान किया है, ताकि भाई-भतीजावाद जैसी प्रवृत्तियों को समाप्त किया जा सके। इस पहल की नींव देश में उभर रही उस व्यापक वैचारिक परिवर्तन पर आधारित है, जिसमें शासन को 'सत्ता' नहीं बल्कि 'सेवा' के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय को 'सेवा तीर्थ', रेस कोर्स रोड को 'लोक कल्याण मार्ग' और ऐतिहासिक 'राजपथ' को 'कर्तव्य पथ' के रूप में नामित किया गया है, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए सूद ने कहा कि अब उनका कार्यालय भी शक्ति का नहीं, बल्कि सेवा का केंद्र है। उद्घाटन अवसर पर पहले बैच के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सूद ने कहा की देश की सोच में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हम 'राज' की औपनिवेशिक मानसिकता से निकलकर 'कर्तव्य' की भावना की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री निवास को 'जन सेवा सदन' कहना हो या प्रधानमंत्री आवास की नई परिकल्पना। संदेश स्पष्ट है कि विधायक या मंत्री का कार्यालय केवल और केवल सेवा के लिए होता है, ताकि नागरिक और सरकार के बीच की दूरी कम हो सके। जनकपुरी के लिए 'स्पेशल 12' , 350 से अधिक आवेदकों में से कठिन चयन प्रक्रिया के बाद चुने गए 12 उत्कृष्ट युवाओं को 'बैच जीरो' के रूप में शामिल किया गया है। इस समूह में चिकित्सक और कानून के छात्र शामिल हैं, जो आगामी तीन महीनों तक जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख शहरी समस्याओं पर कार्य करेंगे। इनमें पंखा रोड पर स्वच्छता ऑडिट, अंधेरे क्षेत्रों की पहचान कर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जैसे जमीनी कार्य शामिल हैं। सूद ने चयनित प्रतिभागियों को 'रील लाइफ' और 'रियल लाइफ' के अंतर को समझने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया संवाद का माध्यम हो सकता है, लेकिन वास्तविक बदलाव जमीन पर होता है। वाईएफजी के फेलोज 'ह्यूमन इंटरफेस' की भूमिका निभाएंगे, जिससे आशीष सूद का कार्यालय जनकपुरी के नागरिकों के लिए एक प्रभावी और परिणामोन्मुख सेवा इकाई बना रहे।

शिक्षा मंत्री ने किया एसओएल के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, मुक्त शिक्षा परिसर के माध्यम से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) एवं ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से "मुक्त, दूरस्थ, डिजिटल एवं मिश्रित शिक्षण में उभरती प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां" विषय पर आयोजित प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन गुरुवार को विज्ञान भवन में किया गया।

इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जबकि समारोह की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की विशाल युवा जनसंख्या को ऑनलाइन, दूरस्थ, डिजिटल एवं मिश्रित अधिगम के माध्यमों से उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना समावेशी राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप शिक्षा का सशक्तिकरण, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख आधार बताया, जिससे युवा नागरिक राष्ट्र के निर्माण में सार्थक योगदान दे सकें। आशीष सूद ने कहा कि भारत की ज्ञान साझा करने की परंपरा मुक्त शैक्षिक संसाधनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्वयं मंच, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय जैसी पहलों में परिलक्षित होती है। ये सुधार उच्च शिक्षा में पहुंच, लचीलापन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हैं तथा भारत को किफायती और व्यापक अधिगम के वैश्विक केंद्र के रूप में सशक्त बनाते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने मुक्त शिक्षा विद्यालय और मुक्त शिक्षा परिसर के माध्यम से समावेशी, लचीली और भविष्य-उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के प्रति विश्वविद्यालय की निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई। कुलपति ने कहा कि यह सम्मेलन नीति संवाद, शैक्षणिक आदान-प्रदान और डिजिटल एवं मिश्रित अधिगम में वैश्विक श्रेष्ठ अनुभवों के साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। मुक्त शिक्षा परिसर की निदेशक प्रो. पायल मागो और मुक्त शिक्षा विद्यालय के प्राचार्य प्रो. अजय जैसवाल ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में नवाचार, गुणवत्ता सुनिश्चितता, शिक्षार्थी सहायता प्रणालियों तथा शिक्षकों की क्षमता निर्माण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप संस्थागत पहलों को सुदृढ़ करता है।

कार्यक्रम के दौरान मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय संघ की प्रथम अध्यक्षीय बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में संसाधन साझा करने, मुक्त शैक्षिक संसाधनों के प्रोत्साहन तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों के माध्यम से सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु रणनीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह को अध्यक्ष तथा मुक्त शिक्षा परिसर की निदेशक प्रो. पायल मागो को महासचिव चुना गया। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के अधिष्ठाता प्रो. बलराम पाणी, डीयू के दक्षिण परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक प्रो. गणेशन कन्नबिरन, लंदन स्थित ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र की निदेशक डॉक्टर लिंडा अमराने कूपर, अंतरराष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद के महासचिव डॉक्टर तोरुन ग्येल्सविक तथा राष्ट्रमंडल अधिगम संगठन के शिक्षा निदेशक डॉक्टर टोनी मेज सहित अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शिक्षाविद, नीति-निर्माता तथा शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, मुक्त शिक्षा विद्यालय तथा मुक्त शिक्षा परिसर द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद और ब्रिटिश परिषद के सहयोग से 29 से 31 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन से पूर्व कार्यशालाएं 28 जनवरी को आयोजित की गईं।

पहाड़गंज होटल में भीषण आग, PS नबी करीम पुलिस बनी फरिश्ता

छत के रास्ते 8 लोगों की जान बचाई

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। पहाड़गंज स्थित एक होटल में देर रात लगी भीषण आग के बीच दिल्ली पुलिस की बहादुरी ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। होटल पल्लवी पैलेस में आग लगने के बाद धुएं और लपटों में फंसे मेहमानों को PS नबी करीम पुलिस टीम ने जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य जिला डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि 28/29 जनवरी की दरम्यानी रात करीब 3 बजे अरकशाना रोड, पहाड़गंज स्थित होटल पल्लवी पैलेस में आग लगने की सूचना मिली। बताया गया कि आग शुरुआत ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन एरिया से हुई, जिसका संभावित कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। चार मंजिला होटल के 18 कमरे धुएं से भर गए और कई मेहमान अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही एसएचओ थाना नबी करीम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालात बेहद खतरनाक थे मुख्य गेट आग की चपेट में था और अंदर से "बचाओ-बचाओ" की आवाजें आ रही थीं। सीधे प्रवेश असंभव था, ऐसे में पुलिस ने तुरंत वैकल्पिक रणनीति बनाई और छत के रास्ते हुआ फिल्मी रेस्क्यू जिसमें कांस्टेबल फेरू, संजय और मुकुल ने असाधारण साहस दिखाते हुए पास के होटल चंचल की चौथी मंजिल से छत पर चढ़कर पल्लवी पैलेस की छत तक रास्ता बनाया। तीन मेहमान बालकनी में फंसे थे, जो पास की बिल्डिंग में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोहे की ग्रिल और कांच की दीवार रास्ता रोक रही थी। पुलिस टीम ने बाधा तोड़कर उन्हें सुरक्षित निकाला। मौके पर पहुंची 11 फायर टेंडरों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस ने बीएसईएस, पीसीआर व एंबुलेंस सेवाओं के साथ समन्वय बनाए रखा। 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया 3

घायल मिले, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया एक को करीब 60 प्रतिशत जलन दो को लगभग 10 प्रतिशत जलन में थे। दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 203 में सो रहे दो मेहमानों को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। पुलिस ने हर कमरे की जांच कर सुनिश्चित किया कि कोई अंदर न रह जाए। घना धुआं, तेज लपटें और जानलेवा हालात इसके बावजूद पुलिस टीम ने अदम्य साहस, सूझबूझ और तत्परता का परिचय दिया। समय पर रेस्क्यू के कारण बड़ा हादसा टल गया।

विजेंद्र गुप्ता ने शिक्षक पदोन्नति में लैंगिक भेदभाव को लेकर उपराज्यपाल को लिखा पत्र

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) में शिक्षकों की वरिष्ठता एवं पदोन्नति व्यवस्था में कथित लैंगिक भेदभाव के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कराया है।

विजेंद्र गुप्ता ने अपने पत्र में उदिता (यूनिफाइड डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स) द्वारा प्राप्त एक प्रतिवेदन को अग्रेषित किया है। यह मामला दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में शिक्षकों की पदोन्नति प्रणाली से संबंधित है, जहां अब भी पुरुष एवं महिला शिक्षकों के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूचियां बनाई जा रही हैं।

पत्र में कहा गया है कि लैंगिक विभाजन के कारण, अनुभव और संख्या में आगे होने के बावजूद महिला शिक्षकों को वर्षों तक पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जबकि पुरुष शिक्षकों को अपेक्षाकृत शीघ्र पदोन्नति मिल जाती है। परिणामस्वरूप अनेक महिला शिक्षक एक ही पद पर लंबे समय तक कार्यरत रहने के बाद बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाती हैं।

पत्र में इस बात का उल्लेख है कि मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और विभाग द्वारा पूर्व में यह संकेत भी दिया गया था कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों की अलग-अलग वरिष्ठता सूचियों को एकीकृत किया जाएगा, इसके बावजूद पदोन्नतियां अभी भी पुरानी लैंगिक-आधारित प्रणाली के अंतर्गत की जा रही हैं। इससे यह आरोप सामने आए हैं कि यह प्रक्रिया महिला शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव करती है और सार्वजनिक सेवा में समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल से इस विषय में हस्तक्षेप करने तथा शिक्षा निदेशालय को लैंगिक भेदभाव समाप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने वरिष्ठता सूचियों के तत्काल एकीकरण तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि सभी पदोन्नतियां समानता, न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप की जाएं।

संपादकीय

आम आदमी की उम्मीद पर कितना खरा उतरेगा बजट

बजट से पहले संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में यह रिपोर्ट पेश की। जबकि एक दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया था। यह सर्वेक्षण पूरे वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के अध्ययन पर आधारित होता है। जिसमें कहा गया है कि घरेलू कारकों की मजबूती और मैक्रो इकॉनॉमिक स्थिरता के चलते विकास से जुड़े खतरे फिलहाल संतुलित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक सकल उत्पादन की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 फीसदी के बीच रहने की संभावना है। सर्वे में कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर 6.5 प्रतिशत आंकी गई थी। पिछले कुछ वर्षों के सुधारों के बाद यह स्पष्ट है कि भारत की उत्पादन क्षमता मजबूत हुई है और विकास की यह संभावना अब 7 प्रतिशत के स्तर को छू रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि बजट में किन क्षेत्रों को राहत मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि यह बजट 'विकसित भारत 2047' के विजन के साथ लंबी अवधि के विकास, राजकोषीय स्थिरता, बुनियादी ढांचे और डिजिटल विकास पर केंद्रित हो सकता है। जिसमें आम जनता के लिए कर राहत और कृषि-केंद्रित उपायों पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब वैश्विक व्यापार तनाव, अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और भू-राजनैतिक अनिश्चितता निजी निवेश पर दबाव डाल रहे हैं। घरेलू स्तर पर, सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास और सामाजिक व्यय को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश अवश्य करेगी। उम्मीद है कि इस बजट में सरकार देश को बाहरी झटकों से बचाने के साथ-साथ घरेलू मांग और विनिर्माण को गति देने के उपायों पर भी गौर करेगी। इस बजट से करदाताओं, खासकर मध्यम वर्ग को, सार्थक राहत की उम्मीद है। महंगाई के कारण दैनिक खर्चों में हो रही भारी वृद्धि से लोग कर छूट बढ़ने व दीर्घकालिक बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वेतनभोगियों व छोटे व्यवसायियों को बजट से वित्तीय तनाव कम होने की उम्मीद है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बजट सत्र की शुरुआत में यह कह चुके हैं कि यह बजट देश के हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर बनाया गया है।

विमान हादसों में नेताओं की असमय विदाई

महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में बारामती–मुंबई–दिल्ली के बीच निरंतर आवाजाही समय की मजबूरी है। ऐसे में चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर नेताओं की पहली पसंद बनते हैं। लेकिन यही विकल्प सबसे अधिक जोखिमपूर्ण भी हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्राइवेट और चार्टर्ड विमानों की दुर्घटना दर कमर्शियल एयरलाइंस की तुलना में कई गुना अधिक है। कारण स्पष्ट हैं—सीमित पायलट अनुभव, पुराने विमानों का उपयोग, मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, अस्थायी हेलीपैड और डीजीसीए की अपेक्षाकृत ढीली निगरानी। अजित पवार की दुर्घटना हो या वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर हादसा, या माधवराव सिंधिया का चार्टर्ड विमान—प्रारंभिक और अंतिम जाँचें बार-बार पायलट त्रुटि, तकनीकी विफलता या प्रतिकूल मौसम की ओर इशारा करती हैं। यह भी स्पष्ट है कि नेता रेल या कमर्शियल फ्लाइट से इसलिए बचते हैं क्योंकि वे चुनावी प्रचार की गति से मेल नहीं खा पातीं। चुनावी मौसम में यह जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

– डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत की राजनीतिक यात्रा बार-बार आकाशी हादसों की भेंट चढ़ती रही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती विमान दुर्घटना ने एक बार फिर पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पांच लोगों की मौत के साथ राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हुआ, जिसकी भरपाई केवल संवेदनाओं से संभव नहीं। यह पहला मामला नहीं है—संजय गांधी (1980), माधवराव सिंधिया (2001), वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (2009) जैसे उदाहरण बताते हैं कि उच्च पदस्थ नेताओं की अकाल मृत्यु बार-बार एक ही प्रश्न खड़ा करती है: क्या विमान हादसे महज़ संयोग हैं, किसी साजिश का परिणाम, या फिर हमारी राजनीतिक यात्रा-संस्कृति और विमानन व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरी? भारतीय राजनीति में हवाई यात्रा अब सुविधा नहीं, बल्कि जीवनरेखा बन चुकी है। चुनावी दौर में एक प्रत्याशी औसतन 120–150 सभाएँ करता है; सप्ताह में 40–50 उड़ानें असामान्य नहीं।

महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में बारामती–मुंबई–दिल्ली के बीच निरंतर आवाजाही समय की मजबूरी है। ऐसे में चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर नेताओं की पहली पसंद बनते हैं। लेकिन यही विकल्प सबसे अधिक जोखिमपूर्ण भी हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्राइवेट और चार्टर्ड विमानों की दुर्घटना दर कमर्शियल एयरलाइंस की तुलना में कई गुना अधिक है। कारण स्पष्ट हैं—सीमित पायलट अनुभव, पुराने विमानों का उपयोग, मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, अस्थायी हेलीपैड और डीजीसीए की अपेक्षाकृत ढीली निगरानी। अजित पवार की दुर्घटना हो या वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर हादसा, या माधवराव सिंधिया का चार्टर्ड विमान—प्रारंभिक और अंतिम जाँचें बार-बार पायलट त्रुटि, तकनीकी विफलता या प्रतिकूल मौसम की ओर इशारा करती हैं। यह भी स्पष्ट है कि नेता रेल या कमर्शियल फ्लाइट से इसलिए बचते हैं क्योंकि वे चुनावी प्रचार की गति से मेल नहीं खा पातीं। चुनावी मौसम में यह जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सैकड़ों हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान किराये पर लिए गए। कई मामलों में रखरखाव प्रमाण-पत्रों, पायलट रेस्ट-नॉर्म्स और हेलीपैड मानकों की अनदेखी सामने आई। राजनीतिक दलों द्वारा लिए जाने वाले तथाकथित 'पॉलिटिकल पैकेज'—कम कीमत, पुराने मॉडल—जोखिम को और बढ़ाते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में केवल नेता ही विमान हादसों में मरते हैं? उत्तर है—नहीं। भारत में हर वर्ष सैकड़ों छोटे विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें आम नागरिक भी मारे जाते हैं। लेकिन मीडिया का फोकस हाई-प्रोफाइल चेहरों पर टिक जाता है।

यही चयन-पूर्वाग्रह है—जो दिखता है, वही पूरा सत्य लगने लगता है। वैश्विक स्तर पर भी यही प्रवृत्ति दिखती है। अमेरिका में जॉन एफ. कैनेडी जूनियर, यूरोप में पोलैंड के राष्ट्रपति लेह काचिंस्की, अफ्रीका और रूस में राष्ट्राध्यक्षों की हवाई दुर्घटनाएँ—हर जगह साजिश की थ्योरी पहले आती है, तथ्य बाद में। जबकि अंतरराष्ट्रीय विमानन आंकड़े बताते हैं कि जनरल एविएशन में अधिकांश दुर्घटनाएँ मानवीय भूल और सिस्टम फेलियर का परिणाम होती हैं। दुर्भाग्य से मीडिया की सनसनीखेज़ी इन हादसों को 'राजनीतिक षड्यंत्र' में बदल देती है। इससे न केवल जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास भी गहराता है। समस्या मूलतः व्यवस्थागत है। डीजीसीए के पास चार्टर्ड विमानों की निगरानी के लिए संसाधन सीमित हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश मौजूद हैं, पर उनका प्रवर्तन कमजोर है। पायलट प्रशिक्षण, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और अस्थायी हेलीपैड—तीनों में गंभीर सुधार की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि शोक के बाद भूलने की परंपरा छोड़ी जाए। इसके लिए कुछ ठोस और व्यावहारिक कदम अनिवार्य हैं। सबसे पहले, राजनेताओं के लिए एक डेडिकेटेड एयर विंग विकसित किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय वायुसेना का वीवीआईपी बेड़ा संचालित होता है, जिसमें आधुनिक हेलीकॉप्टर, उन्नत जीपीएस-रडार सिस्टम और अत्यधिक प्रशिक्षित पायलट हों।

दूसरा, चुनावी मौसम में उपयोग होने वाले चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए सख्त राष्ट्रीय मानक तय किए जाएँ और उनकी रियल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य की जाए, ताकि सुरक्षा से कोई समझौता न हो। तीसरा, नेताओं की अत्यधिक यात्रा को कम करने के लिए वर्चुअल रैलियों, डिजिटल संवाद और तकनीक आधारित प्रचार को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे अनावश्यक उड़ानों का दबाव घटे। चौथा, पायलट प्रशिक्षण, उड़ान से पहले तकनीकी जाँच और विमान रखरखाव पर जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली प्राइवेट कंपनियों पर कठोर दंड लगाया जाए। अंततः, मीडिया के लिए भी जिम्मेदार रिपोर्टिंग संबंधी स्पष्ट गाइडलाइंस तय हों, ताकि हर विमान हादसे को साजिश में बदलने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। नेताओं की असमय मृत्यु केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं होती—वह सत्ता संतुलन, नीतिगत निरंतरता और लोकतांत्रिक भरोसे को भी चोट पहुँचाती है। अजित पवार, वाई.एस.आर. या संजय गांधी—हर हादसा हमें चेतावनी देता है। विमान दुर्घटनाएँ साजिश नहीं, बल्कि लापरवाही, दबाव और कमजोर व्यवस्था का परिणाम हैं। अगर आज सुधार नहीं हुआ, तो कल शोक केवल दोहराया जाएगा। लोकतंत्र के पायलटों को सुरक्षित आकाश चाहिए—यह केवल एक भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि समय की ठोस माँग है। बार-बार होने वाले विमान और हेलीकॉप्टर हादसे यह स्पष्ट कर चुके हैं कि समस्या किसी एक नेता, एक दल या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी राजनीतिक यात्रा-संस्कृति और विमानन व्यवस्था की गहरी संरचनात्मक कमजोरी से जुड़ी है। जब लोकतंत्र के प्रतिनिधि असुरक्षित साधनों से यात्रा करने को मजबूर होते हैं, तो उसका दुष्परिणाम केवल एक परिवार या दल नहीं, बल्कि पूरे शासन तंत्र को भुगतना पड़ता है। नेताओं की असमय मृत्यु सत्ता में शून्य, नीतियों में अस्थिरता और जनता के भरोसे में दरार पैदा करती है। इसके साथ ही साजिश की अफवाहें लोकतांत्रिक संस्थाओं को और कमजोर करती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हर हादसे के बाद संवेदना व्यक्त कर आगे बढ़ जाने के बजाय, ठोस सुधारों को राजनीतिक इच्छा-शक्ति से जोड़ा जाए।

सुरक्षा मानकों में ढील, निगरानी की कमजोरी और जल्दबाजी में की गई उड़ानें किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकती हैं। यदि भारत सचमुच मजबूत और स्थिर लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसे अपने प्रतिनिधियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। सुधार आज होंगे, तभी कल शोक की पुनरावृत्ति रुकेगी। सुरक्षित आकाश केवल नेताओं के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की निरंतर उड़ान के लिए अनिवार्य है।

सुनो नहरों की पुकार : जब आस्था पर्यावरण से संवाद करती है

-डॉ. प्रियंका सौरभ-

आज जब हम पूजा, परंपरा और श्रद्धा की बात करते हैं, तो अक्सर भूल जाते हैं कि धर्म का मूल उद्देश्य जीवन की रक्षा है-विनाश नहीं। जल, जो जीवन का आधार है, वही यदि हमारी आस्था के नाम पर अपवित्र हो जाए, तो यह आत्ममंथन का विषय बनता है। "सुनो नहरों की पुकार" ऐसा ही एक जनजागरण अभियान है, जो हमें हमारी ही भूलों से रूबरू कराता है और बताता है कि सच्ची पूजा क्या है। नहरें सिर्फ़ पानी का बहाव नहीं हैं। वे खेतों की हरियाली, पशुओं की प्यास, गाँवों की संस्कृति और सभ्यता की धमनियाँ हैं। इन्हीं नहरों के सहारे किसान अपने खेतों में सोना उगाता है, पशु जीवन पाते हैं और ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था चलती है। परंतु आज यही जीवनरेखाएँ हमारी असावधानी और अंधी परंपराओं के कारण कराह रही हैं।

पूजा के बाद की सामग्री-मूर्तियाँ, फूल, कपड़, प्लास्टिक, सिंदूर, अगरबत्ती, नारियल, यहाँ तक कि मृत पालतू पशु-नहरों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। जो कर्म श्रद्धा के नाम पर किए जाते हैं, वे दरअसल प्रकृति के विरुद्ध अपराध बन चुके हैं।

इसी पीड़ा और चिंता से जन्मा "सुनो नहरों की पुकार" अभियान। इसकी शुरुआत रोहतक में डॉ. जसमेर सिंह हुड्डा (संयोजक) और हिसार में माननीय भूपेंद्र सिंह गोदारा के प्रयासों से हुई। यह कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या और निरंतर जागरूकता का परिणाम है। यह अभियान न किसी राजनीतिक लाभ के लिए है, न किसी संगठनात्मक प्रसिद्धि के लिए। इसका उद्देश्य केवल एक है-नहरों को प्रदूषण से मुक्त करना और समाज की सोच में बदलाव लाना। गुरेरा गाँव की मिट्टी से उठे मास्टर भूपेंद्र गोदारा ने इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले अनेक जागरूक साथी-सुबेदार मेजर दलीप सिंह, टेकचन्द बागड़ी, श्री दलवीर पोटलिया, रिटायर्ड आचार्य विजेन्द्र सिंह, कृष्ण कुमार, प्राचार्य अजीत सिंह, निहाल सिंह गोदारा, श्री पवन कुमार सहित कई समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता। इन सभी का स्पष्ट विश्वास है कि जब तक समाज अपनी आदतें नहीं बदलेगा, तब तक नहरों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नियम-कानून अपनी जगह हैं, पर वास्तविक बदलाव तभी आएगा जब जनमानस जागेगा। कोरोना जैसे भयावह समय में भी यह कारवाँ नहीं रुका। रविवार हो या छुट्टी, त्योहार हो या बारिश-टीम नहरों के किनारे हाथों में तख्तियाँ लिए खड़ी दिखाई दी। तख्तियों पर लिखे वाक्य केवल नारे नहीं थे, बल्कि समाज से संवाद थे- "जल है तो कल है", "नहरों को प्रदूषित मत करो", "आस्था है तो स्वच्छता भी हो"।

हिम्मत सिंह, राममूर्ति, नरेंद्र कुल्हड़िया, प्रवीण वकील, सुरेंद्र गोदारा, संदीप, सीताराम, शेर सिंह, विकास गोदारा, रामभगत पुनिया जैसे समाजसेवियों ने इस आवाज़ को मजबूती दी। वहीं सुमन गोदारा, संतोष गोदारा, रचना, पुष्पा, कमला, सुनीता, शीला, तारा देवी, सुदेश ढांडा जैसी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने अभियान को सामाजिक गहराई प्रदान की।

गुरेरा से इंस्पेक्टर उदयभान गोदारा ने भी लोगों से आह्वान किया कि जब तक यह संदेश हर गली और हर घर तक नहीं पहुँचेगा, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। जब जीवनदायिनी जलधारा में प्लास्टिक, रसायन और जैविक कचरा घुल जाता है, तो वही जल विष बन जाता है। यह विषाक्त जल खेतों में जाता है, मिट्टी को बीमार करता है, फसलों की गुणवत्ता घटाता है और अंततः हमारे भोजन में प्रवेश करता है।

यह संकट केवल कृषि तक सीमित नहीं है। नहरों का पानी पीने वाले पशु, पक्षी और अन्य जीव रोगग्रस्त हो जाते हैं। जलजनित रोग, त्वचा रोग, पाचन संबंधी समस्याएँ और दीर्घकाल में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए एक मौन आपदा बन चुका है।

"सुनो नहरों की पुकार" अभियान का मूल संदेश सीधा और स्पष्ट है-धर्म का अर्थ है प्रकृति की रक्षा। यदि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो वे नदियों, नहरों, पेड़ों और जीवों में भी हैं। फिर उनकी पूजा के नाम पर इन्हीं तत्वों को दूषित करना कैसी आस्था है? पूजा सामग्री को नहरों में बहाना धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है। मास्टर भूपेंद्र गोदारा का प्रश्न समाज से सीधा संवाद करता है- "हे प्रभु, आपके नाम पर लोग प्रकृति का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? यह कैसी श्रद्धा है, जो जीवनदायिनी नहरों को विष से भर रही है?" यही प्रश्न इस आंदोलन की आत्मा है।

कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं होता, जब तक जनता उसका हिस्सा न बने। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इसने हजारों लोगों की सोच बदली है। अब अनेक स्थानों पर लोग पूजा सामग्री को नहरों में बहाने के बजाय मिट्टी में दबा रहे हैं, पौधों के नीचे रख रहे हैं या जैविक खाद बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।

ये छोटे-छोटे कदम दिखने में साधारण हैं, लेकिन इन्हीं से बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं। जब आदतें बदलती हैं, तभी संस्कृति बदलती है। "सुनो नहरों की पुकार" केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रार्थना है- नहरों को स्वच्छ रखो, जीवन को सुरक्षित रखो। यदि नहरें बचेंगी तो खेत हरे-भरे रहेंगे, पशु-पक्षी सुरक्षित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छ जल का उपहार पाएँगी। यह अभियान हमें याद दिलाता है कि जल ही जीवन है और इसकी रक्षा करना किसी एक व्यक्ति या संगठन की नहीं, बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। आज समय आ गया है कि हम आस्था और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझें। सच्ची श्रद्धा वही है, जो जीवन को बचाए-न कि उसे संकट में डाले। "सुनो नहरों की पुकार" दरअसल हमारी अंतरात्मा की पुकार है। सवाल सिर्फ़ इतना है-क्या हम इसे सुनने को तैयार हैं?

सिद्धबली मंदिर में दर्शन मात्र से पूरी होती है मनोकामना

हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के परम भक्त हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को अतिप्रिय है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो भी जातक मंगलवार के दिन हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित श्री सिद्धबली मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्री सिद्धबली मंदिर में दर्शन करने मात्र से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। वहीं श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद लोग मंदिर में भंडारा करवाते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक गोरखनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। उनको भक्ति आंदोलन का जनक भी माना जाता है। कहा जाता है कि गोरखनाथ को उत्तराखंड के कोटद्वार में सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसकी वजह से उनको सिद्धबाबा कहा जाता है। गोरख पुराण के अनुसार, गोरखनाथ के गुरु का नाम गुरु मछेंद्रनाथ था। बजरंगबली की आज्ञा से वह एक बार त्रिया राज्य की रानी मैनाकनी के साथ रहे थे। जब इस बात की जानकारी गुरु गोरखनाथ को हुई, तो वह अपने गुरु मछेंद्र नाथ को रानी मैनाकनी से मुक्त कराने के लिए चल दिए। बताया जाता है कि सिद्धबली में भगवान हनुमान ने अपना रूप बदलकर गोरखनाथ का रास्ता रोक लिया। जिसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और दोनों ही एक-दूसरे को हरा नहीं पाए। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और गुरु गोरखनाथ से प्रसन्न होकर उन्हें दो वरदान मांगने के लिए कहा। तब गुरु गोरखनाथ ने हनुमान जी से इसी स्थान पर रहकर उनके पहरेदार के रूप में रहने की प्रार्थना की। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस जगह पर सिखों के गुरु गुरु नानक देव और एक मुस्लिम फकीर ने भी पूजा-अर्चना की थी। इस तरह से इस मंदिर का नाम श्री सिद्धबली मंदिर पड़ गया। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है।

आज का इतिहास

1522 - ल्यूबेक और डेनमार्क के बीच युद्ध।
1641 - पुर्तगाल ने मलक्का की खाड़ी व मलाया डचों को सौंप दी।
1648 - स्पेन और हॉलैंड के बीच शांति समझौता हुआ।
1649 - इंग्लैंड के सम्राट 'चार्ल्स प्रथम' को फ़ांसी दी गई।
1788 - ब्रिटेन के राजकुमार' चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट' की रोम में मौत हो गयी।
1790 - लाइफबोट के तौर पर निर्मित पहली नाव का टायन नदी में परीक्षण।
1902 - चीन और कोरिया की स्वतंत्रता के बारे में ब्रिटेन और जापान के बीच पहली 'आंग्ल-जापानी संधि' पर लंदन में हस्ताक्षर हुए।
1903 - लॉर्ड कर्जन ने मेटकाफ हॉल में 'इंपीरियल लाइब्रेरी' का उद्घाटन किया।
1911 - 'कैनेडियन नेवल सर्विस' का नाम बदलकर 'रॉयल कैनेडियन नेवी' किया गया।
1913 - 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' ने आइरिश होम रूल बिल को खारिज किया।
1933 - एडॉल्फ हिटलर ने आधिकारिक रूप से जर्मनी के चांसलर की कमान सम्भाली।
1943 - स्टालिन ग्राफ के पास सोवियत फौजों से जर्मन सेना हारी।
1948 - महात्मा गांधी की हत्या हुई।
1949 - रात्रि एयर मेल सेवा की शुरुआत हुई।
1957 - राष्ट्र संघ ने दक्षिण अफ्रीका को अपनी नस्ल भेदी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।
1964 - दक्षिण वियतनाम में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया।
1971 - इंडियन एयरलाइंस के 'फोकर फ्रेंडशिप विमान' का अपहरण।
1972 - पाकिस्तान ने 'राष्ट्रमंडल' से अपना नाम वापस लिया।
1974 - इंडियन एयरलाइंस के 'फोकर फ्रेंडशिप विमान' का अपहरण हुआ।
1979 - रोडेशिया में नया संविधान बना, जिसमें अश्वेतों को सत्ता में भागीदारी का अधिकार मिला।
1988 - कंबोडिया में 'नरोत्तम सिंहानुक' ने इस्तीफा दिया।
1989 - अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान के काबुल में अपना दूतावास बंद किया।
2005 - वियतनाम में बर्ड फ्लू से 12 लोग मरे।

धार्मिक विवाद में विवेक से काम लें

-संजय गोस्वामी-

26 जनवरी 26 को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना नाम दिए बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप! प्रयागराज माघ मेला में लगाया मौनी अमावस्या के स्नान महोत्सव पर विवाद के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नौवें दिन का व्रत भी जारी हुआ है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिष्यों ने अपने शिविर के बाहर ध्वजारोहण किया और शिष्यों, भिक्षुओं और मठाधीशों के साथ राष्ट्रगान किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए और उप्र सरकार गौ मांस को बाहर में बेचने तथा हिन्दू विरोधी कार्य को करने का आरोप लगाए जिसमें एक बड़ी घटना बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने इस्तीफा देने की वजह यूजीसी के नए नियम और अविमुक्तेश्वरानंद मामले को बताया है।

इसे हम बारीकी से समझते हैं दरअसल प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ से संगम पर स्नान करने के विरोध में पुलिस द्वारा कार्यवाही की नीचे उतारा गया और अपमानित किया गया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद के बाद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं। लंबे समय तक ठंड में रहने के कारण उन्हें सर्दी लगने और बुखार आने के आशंका जताई जा रही है। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के लिए जाते समय मेला प्रशासन की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी रोके जाने के बाद विवाद शुरू हुआ था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों ने प्रशासन पर धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही वह अपने शिविर के बाहर पालकी पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से सार्वजनिक माफी तथा सम्मान स्नान कराए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। वहीं संत समाज की ओर से शांति और संयम बरतने की अपील की गई है। इसे लेकर संतों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों का समाधान टकराव के बजाय बातचीत और आपसी सम्मान से होना चाहिएशिष्य और पुलिसवाले आमने-सामने आ गए।

फिर जमकर धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद शंकराचार्य शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए। शंकराचार्य के शिष्य की पिटाई हुई एसओजी ने अविमुक्तेश्वरानंद के पालकी को ढकेलकर बाहर निकाला द्वारका पीठ के शंकराचार्य बोले- यह गौ हत्या जैसा पाप ॰है और सभी पीठो के शंकराचार्य ने योगी सरकार के कदम का विरोध किया, उधर रामभद्राचार्य बोले- अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्याय किया अब कौन क्या बोल रहा है इस पर शांति से काम लेना चाहिए पहली बात तो ऐ है कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है ऐ समझ में नहीं आता है मारना पीटना किसी को भी शोभा नहीं देता सीखो भगवान राम से जिन्होंने अपने राज़धर्म में किसी जनता पर अन्याय नहीं किया राम को लेकर आए है और इसलिए हमें भी लाइए कितनी बार मैं सुन चुका हूं लेकिन ऐसा नहीं सुना की अहम में अपने को ही भूल गए मैं ही सब कष्टों का कारण है इसे आने ना दो।

पहले सभी सनातन जो हिन्दू धर्म के हित धारक होते है उनके बारे में कुछ जाने सबसे बड़ा सनातनी में सर्वोच्च भाव त्याग का होता है वो भी परमार्थ हेतु, 'मैं' और 'मेरा', ही सर्वनाश की जड़ है पहले उप्र के 2024 में लोकसभा के चुनाव के नतीजे को देखिए बीजेपी मात्र 34 सीट एनडी ए 37 सीट वो भी 80 सीटों उसमें भी कुछ सीट बहुत कम मार्जिन से जिते हैं अतः अब ऐ समय बिल्कुल नहीं है जब राज्य का चुनाव बस अगले साल होने जा रहा हो और एक बार बीजेपी का कोर वोटर जो हिन्दू है वो छींटेगा तो बीजेपी को अगला लोकसभा जितना बहुत मुश्किल होगा अब जब आप सत्ता में रहते हैं तो हर दिन लगता है मेरा ही हुक्म चलेगा लेकिन जिस दिन जनता बदल देगी उस समय लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं इसलिए ऐसी नौबत आने ही ना दो स्वभाव में राजा को राज्य के हित में किसी साधु संत पर मारना पीटना बिलकुल गलत है अतः अब तो उन्होंने सिर्फ माफी मांगने को कहा है मांग लेने में क्या बुराई है जैसे की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने उनके चरणों में नमन बताया ऐ एक अच्छे राज्य प्रशासन की कार्यवाही है वो क्या बोल रहें हैं चुनाव में खड़ा होंगे नहीं होंगे ऐ उनका निजी मामला है इस पर योगी सरकार को क़ोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अब इन सब से शांति से जल्द से जल्द निपटना चाहिए क्योंकि सर पर चुनाव खड़ा है।

वहां स्वर्ण में अधिकांश वोट शंकराचार्य के श्रद्धालु हैं अतः जहां साधु संत हैं वहां तर्क में पड़ना ठीक नहीं है क्योंकि बाद में ऐ मामला पूरे भारत में फ़ैल जाएगी और उसका सीधा असर दूसरे राज्यों के चुनाव पर होगा क्योंकि उनके मानने वाले संस्कृत के विद्वान हैं वो गुरू का साथ देंगे लेकिन मार पीट का नहीं क्योंकि इससे आतंक का माहौल बनता है हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा भी देखा हूं कुछ कटु वचन भी सुना हूं महाकुम्भ में भागदौड़ से हुई सैकड़ो की मौत पर शंकराचार्य ने उप के प्रशासन पर सवाल किए तो उचित था जब आप आयोजन कराते हैं तो किसी भी घटना के लिए वहां का प्रशासन जिम्मेदार होता है एक तो हमें कई बार यह खुले मंच पर सुनने को मिला जो राम को लाएं हैं उसे ही हम लाएंगे ऐ कितना ख़राब है क्या राम मंदिर बनने से सचमुच राम आ गए और क्या पहले भगवान राम नहीं थे और क्या आप भगवान राम से भी ऊपर हो गए की हनुमान जी की तरह कंधे पर बैठाकर लें आए उसका असर ऐ हुई की उप्र में 35 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और दुर्भाग्यवश बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई और अब उसके बाद मोदीजी समझ गए और अब वहां से हटकर राम को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मानकर देश के विकास की बात करते हैं दिवाली में अयोध्या में घी के दिए जलने का रिकॉर्ड बनाते हैं और एक तरफ जनता भूख से मर रही है प्रजा के प्रति दया का होना चाहिए और मजहबी नफरत भी ज्यादा ठीक नहीं होता है इंसान जो भी इंडिया में हो यदि देश प्रेम की भावना हो तो वही भारत के लिए एक एकता की कड़ी है हमें हमेशा बिना मतलब मार पीट से बच कर इंसानियत से काम लेना चाहिए देश में क़ोई भी आतंकी हो उसे कुचलना ही चाहिए लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।

आज भगवान राम में नहीं अपने अपने रथो, महलों में मस्त हैं कौन क्या है ऐ तो जनता बताएगी लेकिन यदि सच्चा राम भक्त देखना है तो हिमालय पर्वत पर मिलेंगे अतः इस पर शांति से काम लेना चाहिए तर्क वितर्क से बचना चाहिए लोगों की भलाई पर काम करना चाहिए ज्यादा ज्ञान है तो शांत मन से उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए लेकिन भारत एक स्वतंत्र देश है मारपीट शोभा नहीं देता हैं। धार्मिक विवाद में विवेक से काम लें क्योंकि क्रोध से किसी पर मार पीट करना बिलकुल शोभा नहीं देता भगवान राम ने कभी किसी को नहीं मारा करुणा और दया के सागर हैं उन्होंने सिर्फ तीर चलाया है वो भी आनंद का भय का नहीं इसलिए रावण भी अन्त समय में भगवान राम से ईश्वर का रूप समझ कर माफी मांग लेता है राम के तीर में जहर नहीं एक प्रकाश था जिसमें दर्द नहीं आनन्द और मोक्ष मिला जिसका जिक्र बाली मोक्ष में भी मिलता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 संपादक - आदित्य वशिष्ठ कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

निजी क्षेत्र की भागीदारी से बढ़ रहा भारत का स्पेस सेक्टर : डॉ. सिंह

नई दिल्ली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि निजी कंपनियां भी इसमें तेजी से अपनी भूमिका मजबूत कर रही हैं। इन स्पेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब तक करीब 1050 निजी कंपनियां विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अपनी क्षमताएं पंजीकृत कर चुकी हैं।

यह आंकड़ा देश में बढ़ते स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। डॉ. जितेन्द्र सिंह गुरुवार को राज्यसभा में स्पेस क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने संबंधी पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 के लागू होने के बाद निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर खुले हैं। इस नीति के तहत निजी कंपनियों को रॉकेट लॉन्च करने, सैटेलाइट का निर्माण और संचालन करने, पृथ्वी अवलोकन, संचार सेवाएँ, डेटा संग्रह और वितरण, साथ ही ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इससे अंतरिक्ष गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और नवाचार को बढ़ावा मिला है। सरकार स्टार्टअप्स और उद्यमियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। अब तक 2.36 करोड़ रुपये की राशि इन-स्पेस सीड फंड और प्री-इनक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत वितरित की जा चुकी है। इस सहायता से नए उद्यमों को तकनीकी विकास और व्यावसायिक विस्तार में मदद मिल रही है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2022 में 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक बढ़ाकर 44 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 11 अरब डॉलर का योगदान निर्यात से आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह रणनीति प्लेटफॉर्म निर्माण, औद्योगिक इकोसिस्टम के विकास, उद्योग को सक्षम बनाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। दशकीय विजन रणनीति तीन प्रमुख स्तंभों- राजस्व सृजन, इकोसिस्टम विकास और अंतरिक्ष गतिविधियों को गति देने पर केंद्रित है। राजस्व बढ़ाने के लिए लॉन्च सेवाओं, सैटेलाइट संचालन, पृथ्वी अवलोकन, सैटेलाइट संचार और नेविगेशन सेवाओं के व्यावसायीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और समावेशी भारत का निर्माणः शिवराज सिंह

नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिह चौहान ने आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उनकी नीतियों से आत्मनिर्भर और समावेशी भारत का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रमाण है पिछले पाँच वर्षों में 4.4 प्रतिशत की औसत कृषि विकास दर- जो अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। गुरुवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 500 की आबादी तक हर गाँव जुड़ा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सभी को गति मिली है। आज लगभग 4 करोड़ आवास बने हैं, आजीविका मिशन से 10 करोड़ से अधिक बहनें जुड़ी हैं और 12 लाख करोड़ रुपये का ऋण उन्हें मिला है।

परिणामस्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और ग्रामीण गरीबी 55 प्रतिशत से घटकर लगभग 11 प्रतिशत रह गई है- यही समावेशी विकास की असली तस्वीर है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश का खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा है, जो हमारी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रमाण है।

आज चावल, गेहूं, मक्का, सरसों और मोटे अनाज में अधिक उपज के कारण हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए हैं बल्कि चावल में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक बने हैं। जो देश कभी आयात पर निर्भर था, वह आज कई मामलों में निर्यातक है- इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्होंने किसानों को बधाई दी।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात कर कहा- सब ठीक

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। संसद भवन स्थित खरगे के कार्यालय में हुई इस बैठक को थरूर ने बहुत सार्थक और सकारात्मक करार दिया।

उन्होंने कहा कि, सब कुछ ठीक है और हम सब एकसाथ आगे बढ़ रहे हैं। बैठक करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चली। थरूर ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का धन्यवाद।

आज कई मुद्दों पर गर्मजोशी और रचनात्मक चर्चा हुई। हम सब एक ही पटल पर हैं और भारत की जनता की सेवा के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद थरूर ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केरल में आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से इनकार करते हुए कहा कि यह उनके लिए कभी मुद्दा नहीं रहा। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल पर कहा कि अपनी ही पार्टी के नेताओं से मिलने में कोई अजीब बात नहीं है।

थरूर ने कहा कि उनका ध्यान तिरुवनंतपुरम की जनता की सेवा और संसद में उनके हितों की रक्षा पर है। कांग्रेस पार्टी में सभी नेता एकजुट हैं और आगे की रणनीति मिलकर तय की जाएगी।

हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए केंद्र योजनाओं से कर रहा हरसंभव सहयोग : गजेन्द्र सिंह शेखावत

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों मनाली, शिमला और धर्मशाला में बढ़ते पर्यटन से पर्यावरण पर पड़ रहे असर तथा भविष्य की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्थिति स्पष्ट की है।

राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार के सवालों के जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रश्नकाल में कहा कि पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार योजनाओं के जरिए उन्हें लगातार सहयोग प्रदान कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप देते हुए स्वदेश दर्शन 2.0 शुरू की है। इस योजना के दिशा-निर्देशों में स्थानीय और जिम्मेदार पर्यटन के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत राज्य सरकारों को पर्यटन परियोजनाएं तैयार करते समय स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक और नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। डॉ. सिकंदर कुमार ने सांस्कृतिक पर्यटन और आध्यात्मिक परिपथों के वैश्विक स्तर पर प्रचार से जुड़े सवाल भी उठाए थे। इस पर गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय भारत को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार में एक मजबूत गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, रोड शो, इंडिया इवनिंग, सेमिनार, टूर ऑपरेटरों को प्रचार सामग्री की सहायता, वैश्विक मीडिया अभियान और एयरलाइंस तथा टूर ऑपरेटरों के साथ संयुक्त प्रचार जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

इन प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों को भी लाभ मिल रहा है। आपदा तैयारी और मजबूत पर्यटन अवसंरचना के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन 2.0 की परियोजनाओं में आपदा-रोधी विशेषताओं को भी शामिल किया गया है। इनमें बेहतर सड़क पहुंच, जल निकासी प्रणाली, मार्ग में आपातकालीन सुविधाएं, सूचना और दिशा बताने वाले संकेतक, संचार सुविधाओं में सुधार, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सीसीटीवी, अंतिम स्थान तक सड़क संपर्क, हेलिपैड और सुरक्षा से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।

यह व्यवस्थाएं हिमाचल जैसे पहाड़ी और आपदा-संवेदनशील राज्यों के लिए खास तौर पर उपयोगी हैं। डिजिटल अवसंरचना को लेकर गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का नया संस्करण शुरू किया है। यह प्लेटफॉर्म एक एआई आधारित टूल का उपयोग करता है, जो यात्रियों को वास्तविक समय में मौसम की जानकारी, शहरों से जुड़ी जानकारी और जरूरी यात्रा सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके जरिए उड़ानें, होटल, कैब, बसें और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों के टिकट भी आसानी से बुक किए जा सकते हैं। इससे हिमाचल प्रदेश के उभरते पर्यटन स्थलों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

झज्जर कोटली क्षेत्र में 21 मवेशी बचाए गए, वाहन जब्त

जम्मू। ऑपरेशन कामधेनु के तहत मवेशी तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक प्रयास को विफल कर बड़ी संख्या में पशुओं को बचाया। 28/29 जनवरी 2026 की दरमियानी रात को झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने नाका प्वाइंट पंजाल पर एक वाहन को रोका जो मवेशियों के अवैध परिवहन में शामिल था। इसके परिणामस्वरूप 21 मवेशियों को बचाया गया और पंजीकरण संख्या जेके03एम -0343 वाले एक ट्रक को जब्त किया गया। वाहन के चालक जिसकी पहचान हार्डवेयर, कोकरनाग, अनंतनाग निवासी सादिक अहमद के पुत्र मुख्तियार अहमद के रूप में हुई है, को हिरासत में लिया गया। तदनुसार झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन में धारा 223 बीएनएस और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत एफआईआर संख्या 15/2026 दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है।

फडणवीस ने बारामती विमान हादसे की जांच कराने की मांग की

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बारामती में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू से को पत्र लिखा है। उन्होंने हादसे की जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है।

इससे पहले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि नई दिल्ली स्थित विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के तीन अधिकारियों की एक टीम और मुंबई स्थित नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के तीन अधिकारियों की एक अन्य टीम आज दुर्घटनास्थल पर पहुंची। एएआईबी के महानिदेशक जीवीजी युगंधर भी बुधवार को घटनास्थल पर पहुंच गए थे।

दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एक संपूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को पुणे जिले में बारामती हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में अजीत पवार और चार अन्य की मौत हो गयी थी।

पिछले एक साल में 2.22 करोड़ लोगों को रोजगार मिला: सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान देशभर में आयोजित 18,000 से अधिक रोजगार मेलों के माध्यम से कुल 2.22 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा को प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।

पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि देश में रोजगार सृजन बढ़ रहा है और बेरोजगारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एकीकृत मंच के रूप में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल की स्थापना की है। मांडविया ने कहा कि पिछले एक वर्ष में देशभर में 18,000 रोजगार मेले आयोजित किए गए और इस अवधि में कुल 2.22 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में एनसीएस पोर्टल को मजबूत किया गया है और वर्तमान में इससे 55 लाख कंपनियां जुड़ी हुई हैं। पिछले 10 वर्षों में रोजगार तलाशने वाले छह करोड़ से अधिक युवाओं ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि एनसीएस पोर्टल को ई-माइग्रेट पोर्टल, युवा-भारत और कौशल विकास मंचों से जोड़ा गया है, ताकि रोजगार के लिए एकल खिड़की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।

मंत्री के अनुसार, बिहार में एनसीएस पोर्टल पर 53 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 39.8 लाख को चुन कर उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए। उन्होंने बताया कि कुल 4.5 लाख युवाओं ने रोजगार मेलों में भाग लिया, जिनमें से 90,000 को चुना गया और केंद्र व राज्य स्तर की कंपनियों ने 43,000 लोगों को रोजगार दिया। अपने लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों, मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियमित रूप से रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय नियोक्ताओं और रोजगार चाहने वालों के बीच संपर्क स्थापित करना है। मंत्री ने बताया कि 20 जनवरी 2026 तक बिहार में एनसीएस परियोजना के तहत 3,280 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 8,492 नियोक्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि एनसीएस पोर्टल पर अंतिम नियुक्ति आंकड़ों की सूचना देना अनिवार्य नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मांडविया ने बताया कि आरबीआई आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में 17 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि 2004-14 के दौरान जहां रोजगार के अवसर 44.23 करोड़ से बढ़कर 47.15 करोड़ हुए, वहीं 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में 64.33 करोड़ रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए।

मंत्री ने कहा कि भारत में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत है, जो विकसित देशों से भी कम है। 'गिग' श्रमिकों से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह रोजगार का एक नया स्वरूप है और एक अनुमान के मुताबिक, देश में करीब दो करोड़ 'गिग वर्कर' कार्यरत हैं।

पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष हुए शामिल

बारामती। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में 66 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस दौरान उपस्थित थे, साथ ही अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा, जो राज्यसभा सदस्य हैं और उनके बेटे पार्थ एवं जय भी मौजूद थे। बारामती से लोकसभा सदस्य एवं अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले और राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी उपस्थित थे। अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए और जब उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाडी से विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में लाया गया तो लोगों ने 'अजित दादा अमर रहे' के नारे लगाए। शाह, गडकरी, नवीन, फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, एकनाथ शिंदे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश सहित कई नेताओं ने पवार के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। पार्थ और जय ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी।

अजित पवार के पार्थिव शरीर को बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी अस्पताल से बृहस्पतिवार की सुबह उनके गांव ले जाया गया। पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर बारामती हवाई पट्टी के पास बुधवार सुबह एक 'लियरजेट' विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अजित पवार की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे में दो पायलट, एक विमान परिचारक और एक निजी सुरक्षा अधिकारी की भी जान चली गई। विमान 'टेबलटॉप रनवे' से महज 200 मीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें पवार समेत विमान में सवार कुल पांच लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में कैप्टन सुमित कपूर भी शामिल हैं, जिनके पास 15,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। 1,500 घंटे का उड़ान अनुभव रखने वाली सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विधिप जाधव और विमान परिचारिका पिंकी माली की भी इस हादसे में मौत हो गई।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उनके पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस विमान दुर्घटना के संबंध में दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की है। सरकार ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में बताया कि सुबह खराब दृश्यता के कारण हवा में एक चक्कर लगाने के बाद 'लियरजेट' विमान को उतरने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, अनुमति मिलने के बाद भी विमान ने हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) को कोई 'रीड-बैक' या प्रतिक्रिया नहीं दी और वह कुछ ही पल बाद रनवे के किनारे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा उसमें आग लग गई। नागर विमानन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि लियरजेट विमान का 'ब्लैक बॉक्स' (जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर शामिल हैं) बरामद कर लिया गया है।

कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार का बड़ा फैसला

15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी करा सकेंगे निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि अब प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी, जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। इस पर समग्र रूप से लगभग 448 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेसवार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित), माध्यमिक शिक्षा परिषद व संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को आईपीडी (अंतःरोगी विभाग) इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उनके आश्रित भी उठा सकेंगे।

प्रेसवार्ता में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।इसी तरह, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक/अंशकालिक शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रेसवार्ता में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना से बेसिक शिक्षा परिषद के 11.95 लाख से अधिक शिक्षक व कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार की इस पहल से प्रति कर्मी करीब 3000 रुपये सालाना प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च अनुमानित है।

कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ साचीज से जुड़े निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले से जो लोग केंद्र या राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

यूपी मंत्रिपरिषद ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के आकस्मिक निधन पर जताया शोक

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिपरिषद ने विगत 28 जनवरी को बारामती, महाराष्ट्र में हुई विमान दुर्घटना में अजित पवार व अन्य लोगों के निधन को अत्यंत दुःखद बताया। कैबिनेट ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत पुण्यात्माओं की शांति की कामना की। कैबिनेट ने कहा कि अजित पवार का असामयिक निधन अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंत्रिपरिषद ने कहा कि अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन में उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से गहरा जुड़ाव रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने तथा महाराष्ट्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी।

उप्र मंत्रिमंडल ने विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास को मंज़ूरी दी, शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को भी मंज़ूरी

मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र नौ फरवरी से शुरू होगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 का राज्य बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए खन्ना ने कहा कि सत्र की शुरुआत नौ फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह परिवार फिलहाल मेरठ जिले में झील की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं। मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए,वित्त और संसदीय कार्य मंत्री खन्ना ने कहा कि अभी मेरठ की मवाना तहसील के नगला गोसाई गांव में रह रहे इन परिवारों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के पालन में दूसरी जगह बसाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत, 50 परिवारों को कानपुर देहात जिले की रसूलबाद तहसील के भैंसया गांव में पुनर्वास विभाग के नाम पर दर्ज 11.1375 हेक्टेयर (27.51 एकड़) जमीन पर बसाया जाएगा, जबकि बाकी 49 परिवारों को ताजपुर तरसौली गांव में 10.530 हेक्टेयर (26.01 एकड़) जमीन पर बसाया जाएगा। हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर 0.50 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे हर बार 30 साल के लिए दो बार बढ़ाया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम पट्टा अवधि 90 साल होगी।

खन्ना ने बताया कि पट्टा तय प्रीमियम या पट्टा किराए के भुगतान पर दिया जाएगा। अन्य अहम फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, खन्ना ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नियोजित शहरी विकास के मकसद से शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दी है। यह नीति भवन मानचित्र की मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाएगी ताकि नियमों का पालन हो सके, साथ ही संशोधित विकास शुल्क भी लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बरेली और मुरादाबाद में साइंस पार्क और तारामंडल की स्थापना को भी मंजूरी दी है। खन्ना ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को भी मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत, आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी आवास और जमीन का पट्टा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अधिकारियों को बहराइच जिले में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जमीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, जिसमें राजस्व गांव परतापुर भी शामिल है, जहां एक दुखद घटना में नदी पार करते समय नौ लोगों की मौत हो गई थी। प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे किया गया और परतापुर गांव के परिवारों को बसाया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को घर दिए जाएंगे, साथ ही जमीन के पट्टे भी दिए जाएंगे। खन्ना ने बताया कि कुल 136 परिवारों को घरों के साथ जमीन के पट्टे दिए जाएंगे, और उनकी खेती की जरूरतों के हिसाब से उन्हें खेती की जमीन भी पट्टे पर दी जाएगी।

यूजीसी के नये नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का रोक स्वागत योग्य : प्रमोद तिवारी

प्रयागराज। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाये जाने का स्वागत किया है। जिसमें यू.जी.सी. के नये नियमों (इक्विटी रेगुलेशन 2026) पर रोक लगा दी है और कहा है कि विशेषज्ञों की एवं स्कॉलर्स की एक समिति बने, और तब तक यू.जी.सी. के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह काम कर रही है, कि 'बांटों और राज करो'। उसी तरह भाजपा सरकार जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटकर राज कर रही है। इसके डीएनए में अंग्रेजों का 'जहर' चला गया है, इसीलिये पिछले लगभग 11 सालों से मोदी सरकार जाति और धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैला रही है। संविधान की शपथ लेकर संविधान की हत्या कर रही है, जिससे लोग जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर बंट जायें और देश की महान जनता का ध्यान, महंगाई, बेरोजगारी, डीजल-पेट्रोल, और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को भूल जाय। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केन्द्र सरकार के चेहरे पर एक 'झन्नाटेदार तमाचा' है। मोदी जी को पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए कि उनकी गलत नीतियों के कारण लोगों में वर्ग संघर्ष फैल गया है। तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार सिद्धान्त को पूरी तरह भूल गयी है। सरकार का काम है कि जहां अशांति हो वहां शांति पैदा करे। किन्तु ये जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर लोगों में आग लगाने का काम कर रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटक जाय। भाजपा सरकार न देश की हितैषी है, न ही देशवासियों की। भाजपा सरकार सत्ता की लालच में किसी भी हद तक गिर सकती है।

देह व्यापार में चार महिला एवं चार पुरुष गिरफ्तार

प्रयागराज। कीडगंज थाना क्षेत्र में मधवापुर बैरहना के पास स्थित एक मकान से अनैतिक देह व्यापार के मामले में 4 पुरुषों एवं 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े आरोपितों के कब्जे से दस मोबाइल फोन एवं 26 कन्डोम एवं 5435 रूपये, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। यह जानकारी गुरुवार को पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के जमीलाबाद गांव निवासी मो. साहिल , नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के बादशाही मंडी निवासी गोविन्द ओझा , कैंट थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड नेवादा मोहल्ला निवासी इन्द्रजीत कुमार पासी , प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के जमीलाबाद निवासी मो. मोईन शामिल हैं । कड़ी गईं 4 महिलाएं भी प्रयागराज जनपद की रहने वाली हैं। सभी महिलाओं के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

हत्या का संदिग्ध आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया; दो पुलिसकर्मी घायल

आगरा। पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को मार गिराया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, हत्या के एक मामले में संदिग्ध बदमाश ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस उप-निरीक्षक की सरकारी पिस्तौल छीनकर गोलियां चलाईं, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में अन्य मुठभेड़ों में हत्या के इसी मामले से जुड़े दो अन्य वांछित अपराधी घायल हो गए, जिन पर भी 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

पुलिस उपायुक्त (नगर) सैयद अली अब्बास ने कहा कि 23 जनवरी को ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के एक होटल में राज चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस अपराध में कई आरोपी शामिल थे। उन्होंने बताया कि संदिग्धों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आगरा जिले के खंदौली निवासी मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अपराध में इस्तेमाल देसी पिस्तौल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने बृहस्पतिवार तड़के एक पुलिस उप-निरीक्षक की पिस्तौल छीन ली और पुलिस दल पर गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की।

लखनऊ में जारी पुलिस बयान के अनुसार, उप-निरीक्षक ऋषि और कांस्टेबल मनोज कुमार गोली लगने से घायल हो गए, जबकि गोलियां ट्रांस यमुना थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार और कोतवाली थाना प्रभारी भानु प्रताप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी लगीं। पुलिस के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में अरबाज खान की छाती और दाहिने पैर में गोली लगी। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दोनों घायल पुलिसकर्मियों को आगरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि

अरबाज का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था। पुलिस ने बताया कि इसी मामले से जुड़ी दो अन्य मुठभेड़ों में अशु नामक अपराधी ट्रांस यमुना इलाके में हुई गोलीबारी में घायल हुआ, जबकि मोहित नामक एक अन्य वांछित आरोपी दौकी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ। घायल आरोपियों के पास से दो देसी पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का आगरा के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अधिकारी को सौंपा। उन्होंने मांग की कि जिस तरह योजनाओं में उनको लगाकर काम कराया जा रहा हैं इसको लेकर उन्हें वैधानिक, सामाजिक, सुरक्षा और सम्मानजनक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पूर्ण कालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करते हुए उनका वेतन दिया जाए। भविष्य निधि पेंशन, महंगाई, भत्ता, मेडिकल अवकाश सहित समस्त वैधानिक लाभ भी दिए जाएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष की जाए तथा कोरोना काल से अब तक सेवानिवृत्ति समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने मुख्य सेविका पद एवं सहायिका से कार्य पद पर योग्य और वरिष्ठता के आधार पर नियमित और समय बाद पदोन्नति करने की भी मांग की है। उन्होंने पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन कार्य के लिए उच्च गुणवत्ता के 5जी मोबाइल फोन की खरीद के लिए कम से कम 20 हजार रुपये और प्रतिमा रिचार्ज के लिए ढाई हजार रुपये डाटा भत्ता की मांग रखी। इस दौरान चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अप्रैल 2026 से पोषण ट्रैकर के साथ-साथ समस्त ऑनलाइन कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। जिलाध्यक्ष बागपत उमा चौधरी ने कहा कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया बाजार भाव के अनुसार सीधे भवन स्वामी के खाते में भुगतान किया जाए और सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

साथ ही निजीकरण और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूर्णता बंद करने की मांग की। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है अगर 7 मार्च तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो 8 मार्च को सभी आंगनबाड़ी लखनऊ कूच करेंगे। धरना प्रदर्शन करने वालों में जिला सचिव बबीता के साथ सैंकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां मौजूद रहीं।

लापता युवक का शव नाले से बरामद

गाजियाबाद। पिछले चार दिनों से लापता 24 वर्षीय एक युवक का शव बृहस्पतिवार को यहां मोदीनगर में एक नाले से बरामद किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान रोरी गांव के रहने वाले रिंकू के रूप में हुई है। रिंकू कुछ दिन पहले घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसके पिता इंद्रजीत ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक, परिवार वालों और स्थानीय लोगों की काफी तलाश के बाद रिंकू का शव एक नाले में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त (मोदीनगर) अमित सक्सेना ने बताया कि मेडिकल जांच के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि रिंकू नशे का आदी था। पुलिस ने बताया कि परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि रिंकू की हत्या कर शव नाले में फेंका गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है।

जिला जेल से बाउंड्री वॉल कूद कर भागे दो कैदी

फरार कैदियों की तलाश में जेल प्रशासन ने लगाई टीमें

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की जिला जेल से गुरुवार को दो कैदी के भागने का मामला सामने आया है। कैदियों के भागने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और उनकी तलाश में टीमें लगा दी गई हैं।

कैदियों के भागने की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर जिला जेल पहुंचे और जांच पड़ताल की। मामले में एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि जिला जेल में कैदी गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी निवासी अमेठी, शेर अली निवासी सुल्तानपुर को तन्हाई बैरक में रखा गया था। दोनों बैरक तोड़कर बाहर निकले और फिर बाउंड्री वॉल कूद कर भागे हैं।

फरार कैदियों में एक मुलजिम हत्या के प्रयास के मामले में व दूसरा दुष्कर्म मामले में जेल में निरुद्ध थे। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें में लगाई गई हैं। जेल में इस घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। वहीं डीएम ने कहा कि मामले में जेल प्रशासन की लापरवाही को लेकर पूछताछ करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व बीते दिनों कन्नौज जिला जेल से भी कैदियों के भागने का मामला प्रकाश में आया था। उस वक्त भी जेल की सुरक्षा व लापरवाही को लेकर जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की गई थी।

जल सहेलियों की अविरल-निर्मल यमुना यात्रा का पचनद संगम से हुआ शुभारंभ, समाज सदैव रहेगा ऋणी: प्रहलाद सिंह पटेल

उरई। यमुना नदी को पुनर्जीवित करने और समाज को नदी संरक्षण से जोड़ने के एक महत्वाकांक्षी अभियान के तहत 'जल सहेलियों' की 'अविरल निर्मल यमुना यात्रा' का गुरुवार को पचनद संगम से औपचारिक शुभारंभ हुआ। यह पदयात्रा एक महीने तक चलेगी और पचनद से दिल्ली तक समाज को यमुना से जोड़ने तथा जनचेतना जगाने का प्रयास करेगी।

बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शिरकत की। उन्होंने नदियों के प्राकृतिक स्वभाव पर जोर देते हुए कहा कि जहां पर्वतों, नदियों का संगम होता है, वहीं जीवन की संभावनाएं जन्म लेती हैं। नदियों का अपना स्वभाव और चरित्र होता है, इसलिए हमें नदियों को उनके

प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार बहने देना चाहिए। जल सहेलियों के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री पटेल ने कहा, जल संरक्षण के लिए जीवन समर्पित करने वाली जल सहेलियों का समाज सदैव ऋणी रहेगा। सरकार लगातार नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए काम कर रही है, अब समाज को उससे जुड़ने की आवश्यकता है। जब नीर-नारी-नदी समान होगी, तभी हम प्रकृति का संतुलन बनाए रख पाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्व प्रसिद्ध जल पुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि नदियों की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। उन्होंने कहा कि आज यह जिम्मेदारी जल सहेलियों ने अपने कंधों पर उठाई है। भारतीय संस्कृति में जल, नदी और नारी का सम्मान था, लेकिन आज गंदा पानी सीधे नदियों में छोड़ा जा रहा है।

नदियों को खतरा केवल शहरी प्रदूषण से ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती रासायनिक खेती से भी है, जिसके प्रति जागरूकता जरूरी है। जालौन के जिलाधिकारी राजेश पांडेय ने इस यात्रा को अत्यंत प्रेरणादायी बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस अभियान में शैक्षिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी नदी संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा सके।

पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

शाहजहांपुर। जनपद के पुवायां थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक महिला ने भांजे और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भंवरे दीक्षा अरुण ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला से पूछताछ कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भंवरे दीक्षा अरुण ने बताया कि गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि भटपुरा चंदू गांव निवासी बलराम (30) की हत्या उसकी पत्नी पूजा ने कर दी है। पुलिस गांव पहुंची, जहां बलराम का शव खून से लथपथ घर के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला। उसकी पत्नी से पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि बीती रात भांजे आदेश और उसके दो अन्य साथियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। भाई राजू का कहना है कि पूजा और आदेश के बीच अवैध सम्बन्ध थे। आरोप है कि अवैध सम्बन्धों के कारण ही पूजा ने आदेश और उसके साथियों के साथ मिलकर बीती रात बलराम की हत्या कर दी। घटना की जानकारी आज सुबह उस वक्त हुई जब वो आज सुबह बलराम के घर पहुंचे। एएसपी ने बताया कि तहरीर मिलते ही प्राथमिकी पंजीकृत की जाएगी। आरोपित महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ।

प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एक दूसरे का सामना करेंगे गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस

वडोदरा। मौजूदा चैंपियन और दो बार की विजेता मुंबई इंडियंस की टीम महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में शुक्रवार को जब गुजरात जायंट्स से भिड़ेगी तो दोनों के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होगा जिससे वह प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित करने की कोशिश करेंगी। गुजरात जायंट्स इस मैच में जीत दर्ज करके लगातार दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में जगह पक्की करना चाहेगा। गुजरात जायंट्स फिलहाल आठ अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट -0.271 है। वह मुंबई इंडियंस (छह अंक, नेट रन रेट +0.146) और दिल्ली कैपिटल्स (छह अंक, नेट रन रेट -0.164) से दो अंक आगे है। गुजरात जायंट्स का भाग्य अब उसके अपने हाथों में है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस पर जीत उसे डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ में जगह दिला देगी, जबकि रिकॉर्ड अंतर से जीत उसे सीधे फाइनल में पहुंचा सकती है। हालांकि मामूली अंतर से मिली हार भी जायंट्स के अभियान को समाप्त कर सकती है। अगर गुजरात जायंट्स शुक्रवार को मुंबई इंडियंस से हार भी जाती है, तब भी उसके प्लेऑफ में पहुंचने की थोड़ी संभावना बनी रहेगी, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब यूपी वॉरियर्स गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और फिर दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे। गुजरात जायंट्स की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने पिछले सभी आठ मुकाबलों में हार चुकी है, जिससे कप्तान एशले गार्डनर का काम और भी मुश्किल हो गया है। उसकी टीम हार के इस सिलसिले को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध होगी लेकिन मुंबई इंडियंस भी अपना रिकॉर्ड और बेहतर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

गुजरात जायंट्स की टीम फिलहाल लय में है। दिग्गज सोफी डिवाइन के शानदार प्रदर्शन से उसने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को तीन रन से हराया था। मुंबई इंडियंस ने भी पिछले मैच में आरसीबी को 15 रन से पराजित किया था जिससे निश्चित तौर पर उसका मनोबल बढ़ा हुआ होगा। मुंबई इंडियंस की तरफ से पिछले मैच में नैट साइवर-ब्रंट ने इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला शतक बनाया था। उन्होंने हेली मैथ्यूज के साथ मिलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। मैथ्यूज ने गेंद से भी अपनी छाप छोड़ी और तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए। मुंबई इंडियंस को इन दोनों विदेशी खिलाड़ियों से फिर से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। मुंबई इंडियंस के लिए यह सकारात्मक पहलू है कि जितनी भी टीम प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में उनमें उसका नेट रन रेट सबसे बेहतर है। ऐसे में अंक बराबर होने पर मुंबई इंडियंस को फायदा मिलेगा जबकि गुजरात जायंट्स हार जाने पर अगर मगर की कठिन डगर में चला जाएगा। अगर हरमनप्रीत की टीम गुजरात जायंट्स से हार जाती है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली अपने आखिरी लीग मैच में यूपी वॉरियर्स से हार जाए। ऐसे में नेट रन रेट मायने रखेगा।

टीम इस प्रकार हैं

गुजरात जायंट्सः एशले गार्डनर (कप्तान), डैनी व्याट-हॉज, बेथ मूनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, शिवानी सिंह (विकेटकीपर), कनिका आहूजा, सोफी डिवाइन, किम गार्थ, अनुष्का शर्मा, आयुषी सोनी, काशवी गौतम, राजेश्वरी गायकवाड़, जिन्तिमणि कलिता, तनुजा कंवर, रेणुका सिंह ठाकुर, जॉर्जिया वेयरहम।

मुंबई इंडियंसः हरमनप्रीत कौर (कप्तान), पूनम खेमनार, हेली मैथ्यूज, राहिला फिरदौस (विकेटकीपर), मिल्ली इलिंगवर्थ, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, नैट साइवर-ब्रंट, सजीवन सजना, निकोला कैरी, संस्कृति गुप्ता, सैका इशाक, शबनीम इस्माइल, क्रांति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, त्रिवेणी वशिष्ठ।

मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

एलिसा हीली की जगह सोफी मोलिनी ऑस्ट्रेलिया की कप्तान नियुक्त

सिडनी। स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर सोफी मोलिनी को गुरुवार को अगले महीने वनडे विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का कप्तान नियुक्त किया गया और इस घरेलू श्रृंखला के बाद वह एलिसा हीली की जगह सभी प्रारूपों में कप्तानी संभालेंगी। हीली ने घोषणा की थी कि भारत के खिलाफ खेलने के बाद वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगी। भारत के खिलाफ वह तीन वनडे और एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगी। भारत के खिलाफ होने वाली श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की सभी प्रारूपों के लिए टीमों की घोषणा गुरुवार को की गई। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 15 फरवरी को सिडनी में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से शुरू होगा। बाकी दो मैच 19 और 21 फरवरी को क्रमशः कैनबरा और एडिलेड में खेले जाएंगे। तीन मैचों की वनडे सीरीज 24, 27 फरवरी और एक मार्च को खेली जाएगी। पहला मैच ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में जबकि अगले दो मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेले जाएंगे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र टेस्ट मैच पर्थ के प्रतिष्ठित वाका ग्राउंड में छह से नौ मार्च तक खेला जाएगा।

इसके बाद मार्च में वेस्टइंडीज के दौरे में मोलिनी सभी प्रारूपों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान होगी। ताहलिया मैकग्रा को उपकप्तान के रूप में बरकरार रखा गया है, जबकि एक अन्य स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर एशले गार्डनर को भी उपकप्तान नियुक्त किया गया है। निकोला कैरी ने सीमित ओवरों के प्रारूप में वापसी की है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल 19 वर्षीय लूसी हैमिल्टन को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

चयनकर्ताओं ने बाएं हाथ की बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड को चोटिल होने के कारण मौजूदा महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) से बाहर होने के बावजूद सभी प्रारूपों में अपनी टीमों में शामिल किया है। अलाना किंग को टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिया गया है। मेगन शट, ग्रेस हैरिस और हीथर ग्राहम वनडे टीम में शामिल नहीं हैं।

भारत के खिलाफ श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस प्रकार हैं:

टी20: सोफी मोलिनी (कप्तान), एशले गार्डनर (उप-कप्तान), ताहलिया मैकग्रा (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।

वनडे: एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनी (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, एशले गार्डनर, किम गार्थ, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्रा, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।

टेस्ट: एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनी (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्रा, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।

टाटा स्टील मास्टर्स: एरिगैसी की एक और हार, गुकेश ने एर्दोगमस को हराया

विज्क आन जी (नीदरलैंड)। भारत के शीर्ष रैंकिंग के खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी महत्वपूर्ण क्षणों में जर्मनी के विन्सेंट कीमर के कौशल का मुकाबला नहीं कर सके और उन्हें टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में एक और हार का सामना करना पड़ा। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने हालांकि युवा खिलाड़ी यागिज कान एर्दोगमस के खिलाफ जीत हासिल करके प्रतियोगिता में वापसी की। काले मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने बाजी जीती। उनके अब संभावित 10 में से पांच अंक हो गए हैं। एरिगैसी कुछ दिन पहले तक शानदार फॉर्म में थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और वह अंक तालिका में निचले पायदान पर हैं। उनके 10 मैचों में सिर्फ चार अंक हैं। टूर्नामेंट के एक अन्य मुकाबले में भारत के आर प्रज्ञाननंदा ने हैंस मोके नीमन के साथ अपनी बाजी ड्रॉ खेली। पिछले दौर में गुकेश को हराने वाले जर्मनी के मैथियास ब्लूबाउम ने अनीश गिरी को हराकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी, जबकि नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फोरस्ट ने जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला।

ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना खुद का इतिहास रचना चाहते हैं जोकोविच

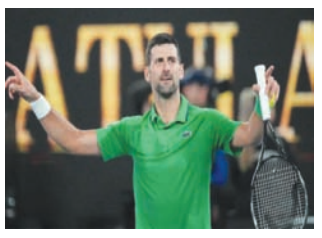

मेलबर्न। पुरुष टेनिस के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में यानिक सिनर के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वह खुद का इतिहास रचने पर ध्यान दे रहे हैं। अब तक रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले जोकोविच जब सिनर के खिलाफ मुकाबले के संदर्भ में सवालों का जवाब दे रहे थे तब एक सवाल पर उन्हें अपमान महसूस हुआ। जोकोविच वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 11वां खिताब जीतने की कवायद में हैं। जोकोविच से उस दौर से तुलना करने के लिए कहा गया जब उन्होंने टेनिस जगत में कदम रखा था तथा उस समय रोजर फेडरर और राफेल नडाल शीर्ष पर थे और अब जबकि सिनर और कार्लोस अल्काराज़ ने पिछले दो सत्र से उन्हें कोई भी ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से रोक रखा है। जोकोविच ने सवालिया अंदाज में कहा, ''मैं यानिक और कार्लोस का पीछा कर रहा हूं। किस अर्थ में। मैं हमेशा पीछा करने वाला खिलाड़ी ही रहा हूं। मेरा कभी पीछा नहीं किया जाता।'' उन्होंने कहा, ''मुझे यह थोड़ा अपमानजनक लगता है कि आप उस दौर के बीच की घटनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं जब मैंने आपके अनुसार राफा और रोजर का पीछा करना शुरू किया था और अब मैं कार्लोस और यानिक का पीछा कर रहा हूं। शायद बीच में लगभग 15 साल का ऐसा समय था जब मैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए हुए था।'' जोकोविच ने कहा, ''इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना महत्वपूर्ण है। सच कहूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी का पीछा कर रहा हूं। मैं अपना खुद का इतिहास रच रहा हूं।'' ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पुरुष वर्ग में शीर्ष चार वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं।

कारोबार

संक्षिप्त खबरें

गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी है : संघवी

गांधीनगर। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य, देश भर में पहले स्थान पर है। संघवी ने यहां नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2000-2002 में (गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में) स्वच्छ ऊर्जा के लिए दृष्टिकोण निर्धारित किया था जब नवीकरणीय ऊर्जा को प्रायोगिक माना जाता था। उन्होंने कहा, '' जिसे कभी मजाक समझा जाता था, वह आज गुजरात की ताकत बन गया है। हमने कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन सरकार कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटी।'' संघवी ने कहा, '' नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत पहल करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है और इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में यह राज्य देश भर में पहले स्थान पर है।'' आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य भारत के पवन ऊर्जा उत्पादन में 27.2 प्रतिशत का योगदान देता है। राज्य की कुल बिजली खपत का 64 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय स्त्रोतों से आता है। गुजरात में 7.5 लाख से अधिक घरों ने रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए गए हैं जो भारत के हिस्से का 30 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता राज्य के उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा।

एयरटेल अपने 36 करोड़ ग्राहकों को एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम की मुफ्त सेवा करेगा प्रदान

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने अपने 36 करोड़ ग्राहकों को एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम की मुफ्त पहुंच प्रदान करने की बृहस्पतिवार को जानकारी दी। इससे ग्राहक उच्च गुणवत्ता वाली सोशल मीडिया सामग्री, विपणन सामग्री, लघु वीडियो और अन्य सामग्री डिजाइन कर सकेंगे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कृत्रिम मेधा (एआई)-संचालित डिजाइन उपकरण तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। इससे भारतीय दूरसंचार संचालक अपने डिजिटल परिवेश में उपयोगकर्ता जुड़ाव को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। एयरटेल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि करीब 4,000 रुपये के एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम की एक वर्ष की मुफ्त सेवा से ग्राहक अपनी रचनात्मकता को व्यक्त कर पाएंगे और पेशेवर-गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम 'सब्सक्रिप्शन' सभी एयरटेल ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। इनमें मोबाइल, वाईफाई और डीटीएच ग्राहक शामिल हैं। उपयोगकर्ता एयरटेल थैंक्स ऐप में 'लॉग इन' करके भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

केरल बजट: विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनहितकारी योजनाओं की घोषणा

तिरुवनंतपुरम। केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2026-27 के लिए बृहस्पतिवार को जन-केंद्रित बजट पेश किया। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों की मदद के लिए 14,500 करोड़ रुपये की भारी राशि और कई नए सामुदायिक कार्यक्रमों के वित्तपोषण का प्रस्ताव है। उन्होंने राज्य के बजट में 12वें वेतन संशोधन आयोग की भी घोषणा की। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन की प्रत्येक पांच साल में समीक्षा करने की लंबे समय से चली आ रही नीति जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन नीत दूसरी सरकार का छठा बजट पेश करते हुए बालगोपाल ने विधानसभा में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह जबकि आंगनवाड़ी सहायकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की।

उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के पूर्व शिक्षकों और साक्षरता अभियान के प्रेरकों (मोटिवेटर) के वेतन में 1,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि जबकि विद्यालय के रसोइया कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में 25 रुपये प्रति दिन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। बजट में मुख्यमंत्री की स्त्री सुरक्षा योजना के लिए 3,700 करोड़ रुपये की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा, बजट में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन में वृद्धि, स्कूली बच्चों सहित सभी श्रेणियों के लोगों के लिए जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और कला एवं विज्ञान कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त डिग्री शिक्षा की भी घोषणा की गई है। बजट में तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) से संबंधित प्रारंभिक कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की गई, जिसे बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। इसमें तटीय क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

राज्य के बजट में वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की घोषणा भी की गई। बालगोपाल ने बजट भाषण में केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र केरल का गला घोंट रहा है और उसके कर राजस्व में कटौती कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, '' घोर उपेक्षा के बावजूद केरल ने प्रगति की है।''

उन्होंने राज्य के बजट में 12वें वेतन संशोधन आयोग की भी घोषणा की। इसमें 12वें वेतन संशोधन आयोग से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। बजट में यह भी पुष्टि की गई है कि कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के सभी लंबित महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान कर दिया जाएगा। एक किस्त फरवरी के वेतन के साथ और शेष बकाया मार्च के वेतन के साथ दिया जाएगा।

पेंशन के संबंध में, वित्त मंत्री ने औपचारिक रूप से सुनिश्चित पेंशन योजना की घोषणा की जो पात्र कर्मचारियों के लिए अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का स्थान लेगी। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत तक प्राप्त होगा, जिसमें डीआर भी शामिल होगा। बालगोपाल ने कहा, '' बजट का उद्देश्य केरल की विकास यात्रा को जारी रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित वेतन एवं वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।''

मजबूती के नए शिखर पर पहुंची चांदी, चेन्नई में भाव 4.25 लाख रुपये के स्तर तक पहुंचा

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में हाजिर चांदी ने एक बार फिर जबरदस्त छलांग लगाई है। शुरुआती कारोबार में आई जोरदार तेजी के कारण ये चमकीली धातु लगातार चौथे दिन मजबूती के नए शिखर पर पहुंच गई है। चांदी के भाव में आए उछाल के कारण ये चमकीली धातु आज देश के ज्यादातर हिस्सों में चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई है।

देश के अलग अलग हिस्सों में चांदी 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 30,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगी हो गई है। भाव में आई इस तेजी के कारण देश के अलग अलग सर्राफा बाजारों में चांदी 4,09,800 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 4,25,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक के भाव पर बिक रही है। दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी 30,000 रुपये प्रति किलोग्राम उछल गई, जिसके कारण ये चमकीली धातु आज चार लाख का स्तर पार कर 4,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसी तरह मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता में चांदी 4,09,800 रुपये के भाव पर कारोबार कर रही है। जबकि जयपुर, सूरत और पुणे में चांदी 4,10,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। वहीं बेंगलुरु में चांदी 4,10,300 रुपये के स्तर पर और पटना तथा भुवनेश्वर में 4,09,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसके अलावा हैदराबाद में चांदी 25,100 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 4,25,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। देश में चांदी की सबसे अधिक कीमत आज भी चेन्नई में है, जहां ये चमकीली धातु आज 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी होकर 4,25,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। मार्केट एक्सपर्ट मयंक मोहन का कहना है कि वैश्विक स्तर पर मची हलचल सोना और चांदी की कीमत को सपोर्ट कर रही हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ को लेकर मनमाना रवैया अपनाने की वजह से निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ है। किसी भी जोखिम से बचने के लिए निवेशक सोना और चांदी जैसे सेफ इनवेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की ओर रुख कर रहे हैं।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 की मुख्य बातें

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश की।

इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

- वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 7.4 प्रतिशत और सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- भारत की संभावित वृद्धि दर लगभग सात प्रतिशत आंकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।
- केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2024-25 (अस्थायी) में बढ़कर जीडीपी के 9.2 प्रतिशत पर पहुंच गईं।
- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां सितंबर, 2025 में घटकर 2.2 प्रतिशत पर आ गईं, जो कई दशक का निचला स्तर है।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत मार्च, 2025 तक 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान 2.35 करोड़ डीमैट खाते जोड़े गए, जिससे इनकी कुल संख्या 21.6 करोड़ से अधिक हो गई। सितंबर, 2025 में विशिष्ट निवेशकों की संख्या 12 करोड़ के पार पहुंच गई जिनमें लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- भारत की वैश्विक वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी 2005 से 2024 के बीच एक प्रतिशत से करीब दोगुनी होकर 1.8 प्रतिशत हो गई।
- सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 387.6 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।
- भारत दुनिया में धन प्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है, जहां वित्त वर्ष 2024-25 में यह प्रवाह बढ़कर 135.4 अरब डॉलर हो गया।
- 16 जनवरी, 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 अरब डॉलर हो गया, जो 11 माह के आयात और 94 प्रतिशत बाह्य ऋण के लिए पर्याप्त है।
- अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति औसतन 1.7 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 35.77 करोड़ टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख टन अधिक है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शुरुआत से अब तक 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पात्र किसानों को जारी की जा चुकी है।
- 'विकसित भारत-जी राम जी', महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का एक व्यापक वैधानिक सुधार है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना है।
- वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए क्रमशः 7.72 प्रतिशत और 9.13 प्रतिशत बढ़ा, जो संरचनात्मक सुधार को दर्शाता है।
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 14 क्षेत्रों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश आकर्षित हुआ है। इससे 18.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री और 12.6 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं (सितंबर, 2025 तक)।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 10 परियोजनाओं से घरेलू क्षमता मजबूत हुई है।
- उच्च गति गलियारे वित्त वर्ष 2013-14 के 550 किलोमीटर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में 5,364 किलोमीटर हो गए, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन जोड़ी गई।
- भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, जहां हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 164 हो गई।
- बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए ऐतिहासिक मोड़ आया है जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में पहली बार 2,701 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

'हेरा फेरी 3' को लेकर परेश रावल ने किया बड़ा खुलासा

बॉलीवुड की चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी 3' लंबे समय से अपनी स्टारकास्ट से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब अभिनेता परेश रावल ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म की स्थिति और अक्षय कुमार के साथ अपने कथित विवाद पर खुलकर बात की।

अफवाहें थीं कि अक्षय कुमार ने फिल्म अचानक छोड़ने के चलते परेश रावल पर 25 करोड़ रुपये का मानहानि केस कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए परेश ने मजाकिया अंदाज में कहा, ₹वो सब 'कछुआ छाप अगरबत्ती' है,₹ यानी बेकार की बातें। उन्होंने साफ किया कि फिल्म 100 प्रतिशत बन रही है और उनके व अक्षय के बीच किसी तरह की कानूनी लड़ाई नहीं है।

परेश रावल ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म के अटकने के पीछे उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि देरी का कारण उनके और अक्षय के बीच कोई झगड़ा नहीं, बल्कि अक्षय कुमार और फिल्म के निर्माताओं के बीच कुछ तकनीकी और कागजी मसले हैं। जैसे ही ये मुद्दे सुलझेंगे, फिल्म पर काम आगे बढ़ जाएगा। परेश ने साफ संकेत दिया कि वह फिल्म के लिए पूरी तरह तैयार हैं। परेश रावल ने पहले भी कहा था कि 'बाबू भैया' का किरदार 'हेरा फेरी' की पहचान है। उनके मुताबिक, अगर यह किरदार फिल्म में नहीं हुआ तो दर्शकों को वो मजा नहीं आएगा और फिल्म को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 'हेरा फेरी 3' में एक बार फिर राजू (अक्षय कुमार), श्याम (सुनील शेट्टी) और बाबूराव (परेश रावल) की आइकॉनिक तिकड़ी साथ नजर आए।

मोना सिंह और बरुण सोबती की सीरीज 'कोहरा 2' का ट्रेलर रिलीज

चर्चित क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'कोहरा' का दूसरा सीजन दर्शकों के मनोरंजन के लिए वापसी कर रहा है। इस बार सीरीज में अभिनेता बरुण सोबती के साथ अभिनेत्री मोना सिंह अहम किरदार में नजर आएंगी। दोनों मिलकर एक नए और खतरनाक केस का पर्दाफाश करेंगे और अपराधियों को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। मेकर्स ने हाल ही में 'कोहरा 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस में रिलीज को लेकर जोश और उत्साह तेजी से बढ़ गया है। सीरीज का निर्देशन सुदीप शर्मा और फैसल रहमान ने मिलकर किया है। सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर ट्रेलर'कोहरा 2' का ट्रेलर करीब 2 मिनट 3 सेकंड लंबा है, जिसमें शुरुआत एक लड़की की रहस्यमयी मौत से होती है। इस बार कहानी पंजाब के एक छोटे शहर की पृष्ठभूमि में सेट है, जहां क्राइम की गुत्थियों को सुलझाने के लिए कमांडिंग अधिकारी धनवंत कौर (मोना सिंह) को तैनात किया जाता है। उनके साथ सहायक सब-इंस्पेक्टर अमरपाल गरुंडी (बरुण सोबती) खतरों और रहस्यों से भरे मिशन पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ट्रेलर में थ्रिल, सस्पेंस और अपराध की अनसुलझी परतों को शानदार तरीके से पेश किया गया है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का वादा करता है। 11 फरवरी को होगी स्ट्रीम'कोहरा 2' नेटफ्लिक्स 11 फरवरी पर स्ट्रीम होगी। पहले सीजन की सफलता के बाद इस नए सीजन को भी फैंस का भरपूर प्यार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर बरुण और मोना की नई जोड़ी और कहानी की रहस्यमयी गहराई के कारण। अगर आप थ्रिलर और क्राइम कहानी के शौकीन हैं, तो 'कोहरा 2' इस बार आपके लिए फरवरी का एक बड़ा वेब ट्रीट बनने जा रही है।

बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' की रफ्तार पड़ी धीमी

आइकॉनिक वॉर फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल 'बॉर्डर 2' इन दिनों सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने 23 जनवरी को रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत की थी। लंबे वीकेंड का फायदा उठाने के बाद अब वर्किंग डेज में फिल्म की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन कुल आंकड़े अब भी दमदार बने हुए हैं। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। छठे दिन कलेक्शन में गिरावटफिल्म समीक्षक तरण आदर्श के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के छठे दिन 15.04 करोड़ रुपये का कारोबार किया। यह आंकड़ा पांचवें दिन की 22.31 करोड़ रुपये की कमाई से कम है, जिससे साफ है कि वीकडे इफेक्ट देखने को मिला है। हालांकि शुरुआती दिनों की जबरदस्त कमाई ने फिल्म को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। पहले दिन 32.10 करोड़, दूसरे दिन 40.59 करोड़, तीसरे दिन 57.20 करोड़ और चौथे दिन 63.59 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन अब लगभग 231.83 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ाछह दिनों के कलेक्शन के मामले में 'बॉर्डर 2' ने कई चर्चित फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। इसने 'छावा', 'सुल्तान' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्मों के शुरुआती 6 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। अब फिल्म की नजर 250 करोड़ क्लब पर टिकी है। आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर इसे रानी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी 3' से मुकाबला करना होगा, जो 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है। ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि देशभक्ति से भरी यह कहानी अभी और लंबी रेस दौड़ सकती है।

'डॉन 3' पर ब्रेक, 'जी ले जरा' को आगे बढ़ाएंगे फरहान अख्तर

फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'डॉन 3' पिछले काफी समय से चर्चा में है, लेकिन इसकी कास्टिंग को लेकर जारी असमंजस के बीच प्रोजेक्ट फिर से धीमा पड़ता नजर आ रहा है। रणवीर सिंह के फिल्म से अलग होने की खबरों के बाद अब यह फ्रेंचाइजी अनिश्चितता में घिर गई है। बीच में ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के नामों को लेकर अटकलें भी लगीं, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि फरहान अब अपना फोकस किसी दूसरी फिल्म पर शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, फरहान अख्तर अपनी ड्रीम रोड-ट्रिप फिल्म 'जी ले जरा' को दोबारा ट्रैक पर लाना चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से ठंडे बस्ते में था, लेकिन अब मेकर्स इसे आगे बढ़ाने के मूड में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है और फरहान एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ से संपर्क में हैं, ताकि उनकी उपलब्ध तारीखों को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। दरअसल, 'जी ले जरा' की सबसे बड़ी चुनौती इसकी स्टार कास्ट की डेट्स का तालमेल बैठाना रहा है। तीनों अभिनेत्रियों के व्यस्त शेड्यूल के कारण पहले भी फिल्म की शूटिंग टलती रही है। सूत्रों का कहना है कि अगर तारीखें फाइनल हो जाती हैं, तो फिल्म की शूटिंग 2026 की दूसरी छमाही में शुरू हो सकती है। फरहान फिलहाल इसी दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि 'डॉन 3' की कास्टिंग पर अंतिम फैसला होने में अभी वक्त लग सकता है।